अब प्रदेश में तबादलों में लागू होगा हरियाणा मॉडल!

अभिताभ बच्चन की सिफारिश के बाद सरकार ने शुरु की कवायद

भोपाल, निप्र।

मध्य प्रदेश सरकार तबादले और पदस्थापना की प्रक्रिया में

सुधार करने के लिए जल्द ही हरियाणा मॉडल लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए हरियाणा की तबादला नीति का अध्ययन किया जा रहा है। दरअसल, मध्य प्रदेश में पिछले सालों में की गई तमाम कोशिशों के बाद भी तबादलों की विसंगतियों को दूर नहीं किया जा सका है। हर बार तबादले और पदस्थापना में लेन देन को लेकर सवाल उठते रहे हैं, सरकार की कोशिश है कि तबादले और पदस्थापना को कंप्यूटर आधारित कर तबादलों को **(शेष पृष्ठ सात पर)**

हर साल तय होती है तबादला नीति फिर भी विसंगतियां

प्रदेश में तबादलों को लेकर हर बार नियम तय किए जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी तबादले और पदस्थापना को लेकर खामियां सामने आती रहती हैं। कमलनाथ सरकार के दौरान भी तबादलों को लेकर नीति तय की गई थी। शिक्षा विभाग में ऑनलाइन आवेदन के बाद तबादले किए गए। इसके बाद भी आदिवासी क्षेत्रों के कई स्कूल शिक्षक बिन रह गए और कई जिलों में क्षमता से ज्यादा शिक्षक पहुंच गए।

हरियाणा की तबादला नीति

हरियाणा में नवविवाहित और तलाकशुदा को मनमर्जी की पदस्थापना का नियम है। 5 साल से ज्यादा एक जगह पर पदस्थ होने पर पद खाली श्रेणी में चला जाता है। 5 साल से ज्यादा होने पर आवेदन करना होता है। आवेदन नहीं तो कहीं भी पदस्थापना कर दी जाती है। 300 से ज्यादा पद वाले विभागों में ऑनलाइन तबादला होता है। पूर्व तबादलों की ट्रैकिंग होती है, लंबे समय से जमे कर्मचारी अधिकारियों को सबसे पहले हटाया जाता है। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के तबादलों के अधिकार निश्चित समय अवधि में मंत्री को होते हैं। शिक्षा विभाग में कन्या विद्यालयों में 50 साल से कम उम्र के शिक्षकों को नहीं रखा जाता।

Badri Gautam

अब प्रदेश में तबादलों में लागू ...

लेकर होने वाले संभावित लेन देन पर लगाम लगाई जाए। उल्लेखनीय है कि अपने एक टीवी शो में अभिताभ बच्चन ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पदस्थ एक पुलिस आरक्षक पति पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थ किए जाने की सिफारिश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की थी।

तबादला नीति में कई खामियां

पति-पत्नी की साथ पदस्थापना का नियम है, लेकिन इसका पूरी तरह से पालन नहीं होता। पदस्थापना के बाद कार्यमुक्त नहीं होने की स्थिति में कार्रवाई नहीं की जाती। लंबे समय तक कर्मचारी एक ही स्थान पर जमे रहते हैं। मुख्यालय पर ही रहने का नियम, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं होती। खाली पदों के बावजूद दूसरे स्थानों पर पदस्थापना हो जाती है।

मुख्यमंत्री दे चुके नसीहत, तबादलों की दलाली करने वालों से बचें

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले दिनों हुए मंथन के दौरान सभी मंत्रियों को नसीहत दे चुके हैं कि तबादले और पदस्थापना को लेकर सभी मंत्री बचें। साथ ही अपने आस-पास जो लोग मीठी-मीठी बातें करते हैं और तबादले और पदस्थापना के लिए सिफारिशें करते हैं, ऐसे लोगों को लेकर सतर्क रहें, ऐसे लोग तबादले और पदस्थापना की सिफारिशें कराते हैं और बाहर निकलते ही कहते हैं काम हो गया। इसमें बदनामी मंत्री और सरकार की होती है। पिछली कमलनाथ सरकार तबादलों को लेकर हमेशा भाजपा के निशाने पर रही थी, यही वजह है कि सरकार अपने मंत्रियों को नसीहत दे चुके हैं, ताकि तबादले और पदस्थापना को लेकर सरकार पर उंगलियां ना उठें।

कर्मचारी संगठन के नियमों का हो पालनः मंत्री

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार के मुताबिक सरकार हरियाणा मॉडल पर तबादला नीति लेकर आने की तैयारी कर रही है। इसके लिए तबादला नीति का अध्ययन करने के निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद ही तबादले किए जाएंगे। उनके मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य, पुलिस विभाग में ही 70 फीसदी तक तबादले होते हैं। पिछले साल स्कूल शिक्षा विभाग में भारी तबादले हुए इसकी वजह से आदिवासी क्षेत्रों के कई स्कूलों में शिक्षक ही नहीं बचे, लेकिन इस बार एक नीति के तहत ही तबादले होंगे। उधर राज्य मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक के मुताबिक तबादला नीति को लेकर हर साल नियम बनते हैं, लेकिन समस्या तब पैदा होती है, जब इन्हें नियमों का पालन ना कर तबादले होना शुरू हो जाते है। पसंद के कर्मचारियों को उनकी मनपसंद जगह पर भेजा जाता है।

Badri Gautam

पढ़ाना छोड़ कार्यालयों में बाबूगिरी कर रहे शिक्षक

12000

स्कूल शिक्षा विभाग में पर्याप्त शिक्षक होने के बावजूद उन्हें गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने से कई स्कूल शिक्षक विहिन हो गए हैं। प्रदेश के करीब 18 हजार ऐसे सरकारी स्कूल हैं, जो एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। वहीं कई स्कूलों में प्राचार्य नहीं हैं। इस कारण प्रभारी प्राचार्य प्रबंधन का कार्य देख रहे हैं। प्रदेश के करीब 12 हजार शिक्षक पढ़ाना छोड़कर गैर शैक्षिणक कार्य में लगे हैं। कई शिक्षक विभागीय कार्यालयों में बाबूगिरी कर रहे हैं। हालांकि विभाग की ओर से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति व अटैचमेंट समाप्त कर उन्हें मूल संस्था में लौटने का आदेश कई बार जारी किया गया है, लेकिन फिर भी पालन नहीं हो रहा है। अभी हाल में स्कूल खुलने से पहले स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर शिक्षकों का अटैचमेंट समाप्त कर उन्हें मूल संस्था में संलग्नीकरण करने के निर्देश जारी किए गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बता दें कि विभाग द्वारा सत्र शुरू होने से पहले भी आदेश जारी होते हैं, जिससे एक या दो शिक्षक लौटते हैं, नहीं तो ऐसा ही चलता रहता है।

(कंटेंट : अंजलि राव)

> विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री की भी मंशा है कि शिक्षकों को उनके मूल कार्य से जोड़ा जाए। जल्द ही फिर से इस निर्देश का पालन करवाया जाएगा।
>
> **– केके द्विवेदी**, उपसचिव स्कूल शिक्षा विभाग

7000 प्रतिनियुक्ति

5000 अटैचमेंट

प्रदेश में कुल स्कूल	प्राथमिक
1,22,786	83,890

हायर सेकंडरी	हाइ	माध्यमिक
3,815	4,740	30,341

प्रदेश में कुल सरकारी शिक्षक

1, 75,000 प्राथमिक	
75000 माध्यमिक	
60,000 व्याख्याता	10,000 प्रधानाध्यापक
10,000	प्राचार्य

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की कुल संख्या

1,10,85,000

20 हजार शिक्षकों की भर्ती अटकी

वर्ष 2018 से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अटकी है। उच्च माध्यमिक के 15 हजार और माध्यमिक शिक्षक के 5670 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जानी थी, लेकिन तीन साल बाद भी पूरी नहीं हुई।

विभागों में इतने शिक्षक संलग्न

60	40
राज्य शिक्षा केंद्र	शिक्षण संचालनालय
150	25
मंत्री, विधायक व सांसद	माध्यमिक शिक्षा मंडल

225	500	3000	3000	5000
डीईओ कार्यालय	जिला शिक्षा केंद्र	बीईओ कार्यालय	बीआरसी कार्यालय	जनशिक्षा केंद्रों में ड्यूटी

Badri Gautam

एक शिक्षक के भरोसे प्रदेश के 18 हजार स्कूल, पदस्थापनाओं में नेताओं का दखल, चौपट हो रहा नौनिहालों का भविष्य

स्कूलों में पढ़ाना छोड़ सरकारी दफ्तरों में बाबूगिरी कर रहे प्रदेश के 12 हजार शिक्षक

स्कूल शिक्षा विभाग ने बीस दिन पहले अटैचमेंट समाप्त करने के जारी किए थे आदेश, एक का भी नहीं हुआ निरस्त

Badri Gautam

शहर प्रतिनिधि, भोपाल

स्कूल शिक्षा विभाग में पर्याप्त शिक्षक होने के बावजूद उन्हें गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने से कई स्कूल शिक्षक विहिन हो गए हैं। प्रदेश के करीब 18 हजार ऐसे सरकारी स्कूल है, जो एक शिक्षक के भरोसे चल रहे है। कई स्कूलों में प्राचार्य नहीं है, इस कारण प्रभारी प्राचार्य प्रबंधन का कार्य देख रहे हैं। प्रदेश के करीब 12 हजार शिक्षक पढ़ाना छोड़कर गैर शैक्षिणक कार्य में लगे हैं। कई शिक्षक विभागीय कार्यालयों में बाबूगिरी कर रहे हैं। हालांकि विभाग की ओर से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति व अटैचमेंट समाप्त कर उन्हें मूल संस्था में लौटने का आदेश कई बार जारी किया गया है, लेकिन फिर भी पालन नहीं हो रहा है। करीब बीस दिन पहले 19 दिसंबर को भी आदेश जारी किया था। जिसमें विभाग ने चेतावनी भी दी कि तत्काल प्रभाव से अटैचमेंट समाप्त नहीं किए, तो संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। बावजूद इसके अभी तक किसी के अटैचमेंट व प्रतिनियुक्ति समाप्त नहीं की गई है।

Monday Special

शिक्षकों भी कार्यालयों में मौज, नहीं देनी पड़ेगी दक्षता परीक्षा : शिक्षकों को भी कार्यालयों में कार्य करना ज्यादा पसंद है। कई शिक्षक जो मंत्री, विधायक या अन्य विभागीय कार्यालयों में कार्य कर रहे हैं, वे अब अपने मूल संस्था में लौटना नहीं चाहते हैं। कई शिक्षकों का कहना है कि पढ़ाने से अच्छा कार्यालयों में कार्य करना ठीक है, नहीं तो दक्षता परीक्षा भी देनी पड़ेगी।

अतिथि शिक्षकों की भर्ती के दिए गए निर्देश : स्कूल खुलने से पहले विभाग ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए करीब सात हजार अतिथि शिक्षकों की भर्ती के आदेश जारी किए थे, ताकि अगर बच्चे स्कूल आएं तो शिक्षकों की कमी ना हो पाए। साल 2018 से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अटकी है। उच्च माध्यमिक के 15 हजार और माध्यमिक शिक्षक के 5670 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जानी थी, लेकिन तीन साल बाद भी पूरी नहीं हुई।

यह है स्थिति

प्रतिनियुक्ति	7 हजार
अटैचमेंट	5 हजार

प्रदेश में यह है स्कूल व शिक्षकों की स्थिति

कुल स्कूलों की संख्या	1,22,786
प्राथमिक स्कूल	83,890
माध्यमिक स्कूल	30,341
हाईस्कूल	4,740

डीपीआई में दो दर्जन से ज्यादा शिक्षक

लोक शिक्षण संचालनालय से ही हर साल अटैचमेंट समाप्त किए जाने के आदेश जारी होते है। लेकिन हालत यह है कि डीपीआई में दो दर्जन से ज्यादा शिक्षक अटैच है। जिन्हें अलग-अलग योजनाओं के नाम पर अटैच कर रखा है संस्कृत बोर्ड में बीस साल से कुछ शिक्षक बाबूगिरी कर रहे है। यह हालात मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल, राज्य ओपन के है। भोपाल जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में हर बार प्रतिनियुक्ति कर सालों से जमे शिक्षकों को हटाने की बात की जाती है, लेकिन प्रस्ताव बनाकर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।

विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले निकाले जाते है आदेश

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विधानसभा का सत्र या स्कूलों का शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पहले अटैचमेंट समाप्त करने के आदेश जारी किए जाते है। जिससे एक या दो शिक्षक लौटते हैं, नहीं तो आदेश जारी कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।

विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री की भी मंशा है कि शिक्षकों को उनके मूल कार्य से जोड़ा जाए। जल्द ही फिर से इस निर्देश का पालन करवाया जाएगा।

केके द्विवेदी, उपसचिव, स्कूल शिक्षा विभाग

स्कूलों के मान्यता नवीनीकरण के आवेदन 31 मार्च तक भर सकेंगे

सुविधा

भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग ने अशासकीय विद्यालयों को मान्यता नवीनीकरण के आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध समस्त अशासकीय विद्यालय आगामी समय सीमा में मान्यता नवीनीकरण के ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। मान्यता नवीनीकरण शुल्क एकमुश्त या तीन किश्तों में जमा किए जा सकेंगे। राज्य शासन ने कोविड-19 संक्रमण और छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया है। इसके पूर्व ऑनलाइन आवेदन अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 निर्धारित की गई थी। जिन अशासकीय विद्यालयों ने पूर्व के निदेर्शों के अनुसार सशुल्क आवेदन किए थे और उनकी मान्यता नवीनीकृत की जा चुकी है, उसे यथावत मान्य किया गया है।

Badri Gautam

पीईबी ने सहायक नर्स चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया

एग्जाम

भोपाल। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) ने सहायक नर्स मिडवाइफ ट्रेनिंग चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण चयन परीक्षा (एएनएमटीएसटी)-2020 के लिए इच्छुक उम्मीदवार इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 220 पदों के लिए आयोजित होने वाली ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 से 23 जनवरी तक जारी रहेगी। यह परीक्षा 15 और 16 फरवरी को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।

Badri Gautam

राज्य शिक्षा केंद्र की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज

समीक्षा

भोपाल। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सोमवार को दोपहर 3 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया है। इसमें विभाग की गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। वीसी के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र के अपर संचालक ओएल मंडलोई ने सभी जिला परियोजना समन्वयकों को पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि सभी डीपीसी, सहायक परियोजना समन्वयक एवं बालिका शिक्षा तथा प्रोग्रामर पूरी तैयारी के साथ वीसी में उपस्थित रहें।

Badri Gautam

विद्यार्थियों को होगी सहूलियत

बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए वेबसाइट पर प्रश्न बैंक अपलोड

स्टार समाचार | भोपाल

माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं व बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं 30 अप्रैल से 15 मई तक चलेगी। इस साल दो बार बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर पहली परीक्षा में कोई विद्यार्थी शामिल नहीं हो पाता है तो वह 1 से 15 जुलाई तक चलने वाली दूसरी परीक्षा में शामिल हो सकता है। इस बार माशिमं ने बोर्ड परीक्षा पैटर्न में बदलाव कर ब्लू प्रिंट जारी कर दिया है। साथ ही माशिमं ने नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न बैंक भी अपलोड कर दिया है। इस बार बोर्ड परीक्षा के पेपर प्रश्न बैंक से बनाएं जाएंगे। अब चार माह से भी कम समय शेष है। ऐसे में विद्यार्थियों को प्रश्न बैंक से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। माशिमं ने हर विषय के पूरे पाठ्यक्रम को तीन यूनिट में बांट दिया है। सभी यूनिट से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नपत्र में अब दीर्घउत्तरीय प्रश्नों के बदले छोटे-छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर पूरे चैप्टर को ठीक से समझकर पढ़ने के बाद ही दिया जा सकता है। हर विषय में 100 अंक का प्रश्नपत्र होगा।

18 लाख विद्यार्थी होंगे शामिल

इस बार दसवीं व बारहवीं की परीक्षा में करीब 18 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। दसवीं में करीब साढ़े 10 लाख व बारहवीं में साढ़े सात लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। जबकि हर साल करीब 19 से 20 लाख विद्यार्थी शामिल होते हैं।

कोरोना और राज्य ओपन बोर्ड की 'रुक जाना नहीं' योजना के कारण भी विद्यार्थियों की संख्या कम हुई है। बोर्ड परीक्षा के नए पैटर्न पर आधारित ब्लू प्रिंट और प्रश्न बैंक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। प्रश्न बैंक से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।

–उमेश कुमार सिंह, सचिव, माशिमं

Badri Gautam

सीबीएसई 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं आज से

MCQ होंगे पेपर में, सीबीएसई ने जारी किए बोर्ड के लिए सैंपल पेपर

रिपोर्टर • IamBhopal
Mobile no. 9827080406

सीबीएसई के बोर्ड परीक्षार्थियों के मन की उलझनें अब दूर होंगी। इसके लिए सीबीएसई ने एडवांस सैंपल जारी कर दिया है। इससे 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र के नए पैटर्न की जानकारी मिलेगी। इसमें यह बताया गया है कि केस स्टडी के प्रश्न का उत्तर कैसे देना है। केस स्टडी प्रश्न में क्या पूछा जाएगा। कथन और कारण प्रश्न का फॉर्मेट क्या होता है। इसी आधार पर प्री बोर्ड की परीक्षा शुरू होने जा रही हैं ताकि स्टूडेंट्स को परीक्षाओं की तैयारी की प्रेक्टिस हो जाए। सैंपल पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेशचन (MCQ) को जगह दी गई है, ताकि सही उत्तर देकर पूरे अंक स्कोर करने का मौका स्टूडेंट्स के पास रहे।

सीबीएसई की 10 वीं और 12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षाएं 11 जनवरी से शुरू होने जा रही हैं। भोपाल सहोदय समूह के लगभग 20 स्कूल्स में यह परीक्षा होगी। सभी स्कूल्स ने मिलकर अपना प्रश्न-पत्र बनाने के लिए अपना योगदान दिया और अब उन्हीं क्वेश्चन बैंक के आधार पर तैयार हुए पेपर्स में से सभी स्कूल्स परीक्षा लेंगे। कोविड के चलते किसी भी स्टूडेंट के लिए प्री-बोर्ड को अनिवार्य नहीं किया गया है। जो स्टूडेंट्स परीक्षा देना चाहते थे, उनके पैरेंट्स से कंसेंट लेटर लिया है। जानकारी के मुताबिक लगभग 80 से 90 फीसदी पैरेंट्स ने चाहा है कि उनके बच्चे प्री-बोर्ड दें। पैरेंट्स को भी बताया गया है कि सीमित संख्या में ही स्टूडेंट्स को ही बैठाया जाएगा।

कोविड संक्रमण को देखते हुए एक कक्षा में बैठेंगे सीमित परीक्षार्थी

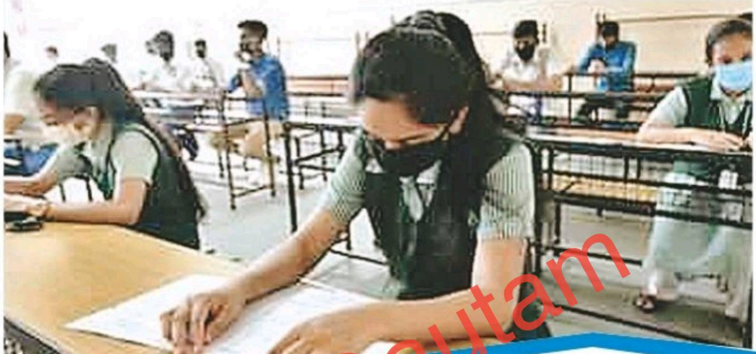

सैंपल पेपर से होगी परीक्षा

90 फीसदी पैरेंट्स अपने बच्चों को प्री-बोर्ड दिलाना चाहते हैं। सीबीएसई द्वारा जारी मार्किंग स्कीम सैंपल पेपर के आधार पर परीक्षा होगी। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया है।
– मीना जैन, पीआरओ, सेंट पॉल स्कूल

अल्टरनेट डे आएंगे स्टूडेंट्स

80 से 90 फीसदी स्टूडेंट्स परीक्षा देंगे। 10 वीं और 12 वीं का पेपर अल्टरनेट डे पर होगा। स्टूडेंट्स को अपना सेनिटाइजर लाने की अनुमति है, साथ ही स्कूल में भी यह व्यवस्था रहेगी। पैरेंट्स को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना ज्यादा कुछ छुए वे परीक्षा देंगे।
– वसुंधरा शर्मा, पीआरओ, सेंट जोसफ को-एड स्कूल

30 फीसदी कम हुआ सिलेबस

हर 15 दिन बाद परीक्षाएं शुरू करेंगे, क्योंकि बोर्ड ने हाल में ही सैंपल पेपर जारी किए हैं, तो उसकी मार्किंग स्कीम देखकर पेपर सेट कर रहे हैं। इस बार 30 फीसदी तक सिलेबस कम हुआ है। **– अजयकांत शर्मा**, मीठी गोविंदराम पब्लिक स्कूल

मुझे स्कूल स्टाफ पर भरोसा

मेरी बेटी 12 वीं बोर्ड की परीक्षा देगी। पहले कोविड से डर था कि बच्चे कैसे मैनेज करेंगे। अब सभी कामों के लिए बाहर जाना ही पड़ रहा है, तो स्कूल भी जा सकते हैं। स्कूल वाले अपनी जिम्मेदारी को बेहतर समझते हैं तो मुझे डर नहीं। **– रीना जैन**, नेहरू नगर

दो प्री-बोर्ड परीक्षा लेने का प्लान है...

बोर्ड एग्जाम मई में होंगे, लेकिन यह समय अभी काफी दूर है। हमने सोचा यदि अभी प्री-बोर्ड नहीं लिया तो स्टूडेंट्स की बोर्ड को लेकर सक्रियता कम हो जाएगी। स्टूडेंट्स की तैयारी में किसी तरह की कमी न आए, इसलिए सहोदय अपना पहला प्री-बोर्ड ले रहा है। इसके बाद अगला प्री-बोर्ड भी होगा, लेकिन अभी उसका महीना तय नहीं किया है। हमने पैरेंट्स की सहमति से ही स्टूडेंट्स का परीक्षा में बैठना सुनिश्चित किया है। प्री-बोर्ड देना अनिवार्य नहीं रखा है, यदि पैरेंट्स चाहे तो परीक्षा दिलाएं। हालांकि हमने स्टूडेंट्स की सुरक्षा के सभी इंतजाम किए है।
– सोजन जोसफ, अध्यक्ष, सीबीएसई सहोदय ग्रुप

सीबीएसई ने जारी किए सैंपल पेपर

10 वीं और 12वीं के हर विषय के प्रश्न पत्र में केस स्टडी पूछी जाएगी। अब केस स्टडी में किस तरह के प्रश्न होंगे, इसकी जानकारी न तो शिक्षकों को और न ही छात्रों को है। इससे जुड़ी कोई किताब भी बाजार में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में बोर्ड ने एडवांस सैंपल पेपर उपलब्ध करवाया है। इसे सॉल्व कर एग्जाम का पैटर्न समझ समझ सकते हैं।

Badri Gautam

ग्रेच्युटी और भविष्य निधि मद में हो सकती है बढ़ोतरी

अप्रैल माह में बदलेंगे कई नियम

कामकाज के 12 घंटे करने की तैयारी में केंद्र सरकार

नई दिल्ली | एजेंसी

1 अप्रैल 2021 से आपकी ग्रेच्युटी, पीएफ और काम के घंटों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और भविष्य निधि (पीएफ) मद में बढ़ोतरी होगी।

नए ड्राफ्ट कानून में कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव पेश किया है। ओएसच कोड के ड्राफ्ट नियमों में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवरटाइम में शामिल करने का प्रावधान है।

रिटायरमेंट पर मिलेगी ज्यादा राशि

ग्रेच्युटी और पीएफ में योगदान बढ़ने से रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि में इजाफा होगा। इससे लोगों को रिटायरमेंट के बाद सुखद जीवन जीने में आसानी होगी। उच्च-भुगतान वाले अधिकारियों के वेतन संरचना में सबसे अधिक बदलाव आएगा।

इसलिए वेतन घटेगा और पीएफ बढ़ेगा

नए ड्राफ्ट रूल के अनुसार, मूल वेतन कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। इससे ज्यादातर कर्मचारियों की वेतन संरचना बदलेगी, क्योंकि वेतन का गैर-भत्ते वाला हिस्सा आमतौर पर कुल सैलेरी के 50 फीसदी से कम होता है। वहीं कुल वेतन में भत्तों का हिस्सा और भी अधिक हो जाता है।

Badri Gautam

एक अप्रैल से 12 घंटे होंगे ऑफिस के घंटे और बदलेंगे पीएफ और रिटायरमेंट के नियम

नई दिल्ली, (एजेंसी)। 1 अप्रैल 2021 से आपकी ग्रेच्युटी, पीएफ और काम के घंटों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नए ड्राफ्ट में कामकाज के अधिकतम घंटों को 12 करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। वर्तमान में नियमानुसार कार्य के अधिकतम घंटे नौ है।

कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और भविष्य निधि (पीएफ) मद में बढ़ोतरी होगी। वहीं, हाथ में आने वाला पैसा (टेक होम सैलरी) घटेगा। यहां तक कि कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होगी। इसकी वजह है पिछले साल संसद में पास किए गए तीन मजदूरी संहिता विधेयक (कोड ऑन वेजेज बिल)। इन विधेयकों के इस साल 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। वेज (मजदूरी) की नई परिभाषा के तहत भत्ते कुल सैलरी के अधिकतम 50 फीसदी होंगे। इसका मतलब है कि मूल वेतन (सरकारी नौकरियों में मूल वेतन और महंगाई भत्ता) अप्रैल से कुल वेतन का 50 फीसदी या अधिक होना चाहिए। गौरतलब है कि देश के 73 साल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से श्रम कानून में बदलाव किए जा रहे हैं। काम के घंटे 12 घंटे करने का प्रस्ताव नए ड्राफ्ट कानून में कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव पेश किया है। ओएसएच कोड के ड्राफ्ट नियमों में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवरटाइम में शामिल करने का प्रावधान है।

Badri Gautam

नए शैक्षणिक सत्र में छठवीं-आठवीं के बच्चे जमीन पर नहीं, बेंच पर बैठेंगे

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। नए शैक्षणिक सत्र में सरकारी स्कूलों के कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों को वेंच में वैठाया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संवंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। विभागीय स्तर पर स्कूल खोलने को लेकर प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में माध्यमिक स्कूलों को फर्नीचर उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है।

नामांकन के आधार पर स्कूलों को मिलेंगे फर्नीचर : एक परिसर एक शाला के स्कूलों में छठवीं से आठवीं तक के विद्यार्थियों का नामांकन एवं विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर फर्नीचर उपलब्ध कराया जाना है। इसके आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इस संवंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने जिला मिशन संचालकों को निर्देश जारी किए हैं। छठवीं से आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर उपलब्ध कराया जाना है। यू-डाइस 2019-20 के अनुसार कक्षा छठवीं से आठवीं तक के विद्यार्थियों का नामांकन एवं विद्यार्थियों की संख्या के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं।

लंबे समय से चल रही थी कवायद : स्कूल शिक्षा विभाग लंवे समय से माध्यमिक स्कूल के विद्यार्थियों को डेस्क-वेंच में वैठाने की कवायद में जुटा था। हालांकि हर वार किसी न किसी कारण से सरकारी स्कूलों में डेस्क-वेंच की व्यवस्था लागू नहीं हो पा रही थी।

जिलेवार जारी किए गए आंकड़े: राज्य शिक्षा केंद्र ने जवलपुर परियोजना समन्वयक सहित प्रदेश के अन्य अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए एक पत्र जारी किया है जिसमें जिलेवार आंकड़ा दिया गया है। आंकड़ों के अनुसार ही जिलों के विद्यार्थियों के लिए डेस्क-वेंच खरीदनी पड़ेगी।

Badri Gautam

बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र किए अपलोड

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 30 अप्रैल से 15 मई तक चलेंगी। इस साल दो बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

अगर पहली परीक्षा में कोई विद्यार्थी शामिल नहीं हो पाता है तो वह एक से 15 जुलाई तक चलने वाली दूसरी परीक्षा में शामिल हो सकता है। इस बार मंडल ने बोर्ड पैटर्न में बदलाव कर ब्लू प्रिंट जारी कर दिया है। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न बैंक भी अपलोड कर दिए हैं। इस बार बोर्ड परीक्षा के पेपर प्रश्न बैंक से बनाए जाएंगे। अब चार माह का समय शेष हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को प्रश्न

तैयारी

- 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बैंक से पूछे जाएंगे प्रश्न
- दोनों बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे 18 लाख विद्यार्थी

Badri Gautam

बैंक से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। माशिमं ने हर विषय के पूरे पाठ्यक्रम को तीन यूनिट में बांट दिया है। सभी यूनिट से प्रश्न पूछे जाएंगे।

प्रश्नपत्र में अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बदले छोटे-छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर पूरे चैप्टर के ठीक से समझकर पढ़ने के बाद ही दिया जा सकता है। हर विषय में 100 अंक का प्रश्नपत्र होगा। इसमें एक, तीन या चार अंक के प्रश्न होंगे।

पहले की तरह पांच, छह या दस अंक के प्रश्न नहीं होंगे। इस बार 10वीं व 12वीं की परीक्षा में करीब 18 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। हालांकि इस बदलाव का कुछ संगठनों ने विरोध भी किया था। कुछ संगठनों का कहना है कि बीच सत्र में इस तरह का बदलाव करना पूरी तरह से गलत है।

> बोर्ड परीक्षा के नए पैटर्न पर आधारित ब्लू प्रिंट और प्रश्न बैंक अपलोड कर दिए गए हैं। प्रश्न बैंक से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।
>
> **- उमेश कुमार सिंह,** सचिव मंडल

बोर्ड परीक्षा में इस बार प्रश्न बैंक से पूछे जाएंगे सवाल, बेवसाइड पर किए अपलोड

नगर संवाददाता | रीवा

कोरोना की वजह से शैक्षणिक सत्र 2020-21 बुरी तरह प्रभावित हुआ। कक्षाएं संचालित नहीं हो पाई। अभी भी क्लासेस पटरी पर नहीं आई हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में बोर्ड परीक्षा करने की तैयारी में है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ऐसी कठिन परिस्थितियो में विद्यार्थियों को राहत देने की योजना तैयार की है। परीक्षा की तैयारी के लिए प्रश्न बैंक वेबसाइडट पर अपलोड किए हैं। ऐसा बताया गया है कि इस बार इसी प्रश्न बैंक से परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे।माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं व बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं पन्द्रह दिन चलेंगी। यह परीक्षा 30 अप्रैल से शुरु करने की तैयारी है, जो 15 मई तक सम्पन्न करा ली जाएगी।

दूसरी बार भी दे सकेंगे परीक्षा

इस बार बोर्ड की परीक्षा दो बार आयोजित होगी। ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि यदि कोई विद्यार्थी पहली बार की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है तो दूसरी बार आयोजित परीक्षा में शामिल हो सकता है। यह परीक्षा 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होगी।

प्रश्नों का पैटर्न भी बदलेगा

कोरोना काल में हो रही बोर्ड परीक्षा में प्रश्नों का पैटर्न भी बदला जा रहा है। प्रश्नपत्र में अब दीर्घउत्तरीय प्रश्नों को शामिल नहीं किया जाएगा। छोटे-छोटे प्रश्न एक, तीन या चार अंक के होंगे।

Badri Gautam

राज्य के कॉलेजों में आज से क्लासरूम में पढ़ाई

- आपस में लंच बॉक्स, पानी की बोतल, नोटबुक, स्टेशनरी भी साझा नहीं कर सकेंगे छात्र
- अभी सिर्फ स्नातक अंतिम वर्ष के 50 प्रतिशत छात्रों को रोटेशन के आधार पर बुलाया जाएगा

भास्कर न्यूज़ | भोपाल

उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सोमवार से थ्योरी क्लास भी लग सकेंगी। हालांकि अभी सिर्फ स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों की क्लासरूम टीचिंग शुरू हो सकेगी। कक्षाओं की उपलब्धता के अनुसार 50 प्रतिशत छात्रों को रोटेशन के आधार पर बुलाया जाएगा। इस दौरान छात्र आपस में पानी की बोतल, नोटबुक, स्टेशनरी, लैपटॉप आदि शेयर नहीं कर सकेंगे। इन चीजों के शेयर करने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इन बातों पर कॉलेज प्रबंधन और शिक्षकों को निगरानी करनी होगी। अभी तक सिर्फ प्रैक्टिकल क्लास आयोजित की जा रही थीं।

उच्च शिक्षा विभाग की एसओपी के अनुसार क्लासरूम में कुर्सियों की डेस्क के बीच 6 फीट की दूरी तय कर बैठक व्यवस्था रहेगी। सभी को पूरे समय मास्क लगाना होगा। भौतिक दूरी के साथ पर्याप्त समय के लिए अलग-अलग स्लॉट में कक्षाओं की गतिविधियों को पूरा किया जाएगा। वहीं कैंपस में छात्र-छात्राएं समूह बनाकर एकत्रित न हो सकें, इसकी विशेष निगरानी करनी होगी। वहीं ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी। इसके लिए फैकल्टी को नवीनतम शिक्षण विधियों का उपयोग करने सहित अपने आप को अपडेट रखने की सलाह दी गई है।

20 से लगेंगी सभी कक्षाएं

उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार 20 जनवरी से भी शेष कक्षाएं शुरू की जा सकेंगी। लेकिन इससे पहले कोविड-19 महामारी के नियंत्रण के लिए जिला स्तर पर गठित क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की अनुशंसा प्राप्त करनी होगी।

Badri Gautam

प्राइवेट इंजीनियरिंग सहित सभी तकनीकी कॉलेज भी आज से खुलेंगे, छात्रों को भेजे गए मैसेज

भोपाल | राज्य शासन की मंजूरी के बाद राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी सरकारी, ऑटोनोमस और निजी कॉलेज खोलने की मंजूरी, 7 जनवरी को आदेश जारी हो चुका है। लेकिन आरजीपीवी के रजिस्ट्रार प्रो. आरएस राजपूत द्वारा इस संबंध में अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। जबकि अकादमिक कार्यों की प्रमुख जिम्मेदारी आरजीपीवी के पास है। सोमवार से री-ओपन हो सकेंगे। शुरुआत में फर्स्ट ईयर के छात्र-छात्राएं शामिल हो सकेंगे। हालांकि शासन के आदेश अनुसार प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में सोमवार से क्लासरूम टीचिंग शुरू हो सकेगी। एसोसिएशन ऑफ टेक्निकल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट (एटीपीआई) के चेयरमैन केसी जैन ने बताया कि फर्स्ट ईयर के सभी छात्रों को मैसेज कर जानकारी दी गई है। शासन की गाइडलाइन के अनुसार सोमवार से कॉलेज खोल जाएंगे। शेष | पेज 12 पर

लाइब्रेरी में सिर्फ किताबें मिलेंगी

- शिक्षक, अधिकारियों, कर्मचारियों और छात्रों को पहचान पत्र पहनना अनिवार्य है।
- लाइब्रेरी का संचालन सिर्फ किताबों का आदन-प्रदान के लिए ही हो सकेगा।
- कैंपस में कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगा। इस पर कॉलेजों को पूरी तरह से रोक लगानी होगी।

बच्चों को वर्चुअल क्विज के द्वारा प्रतिभा दिखाने का मंच दे रहा बायजूस

दुनिया की सबसे मूल्यवान एजूटेक कंपनी बायजूस, सबसे बड़ा डीएसएसएल क्विज आयोजित कर रहा है। बायजूस देशभर के स्टूडेंट्स के लिए वर्चुअल क्विज के जरिए प्रतिभा दिखाने का मौका लेकर आया है। 'डिस्कवरी स्कूल सुपर लीग पावर्ड बाय बाजयूस (डीएसएसएल) से तीस हजार स्कूलों को जोड़ा जाएगा, वहीं करीब एक करोड़ स्टूडेंट्स का जोड़ने का टारगेट रखा गया है। स्टूडेंटस डीएसएसएल एप के जरिए क्विज में हिस्सा ले सकेंगे। स्टेट से क्वालीफाई टॉप टीम को टीवी राउंड का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। कोरोना के चलते इस बार क्विज 100 प्रतिशत वर्चुअल हो रहा है। बायजूस मार्केटिंग हेड के वीपी अतीत मेहता ने कहा कि स्टूडेंट्स अपने फेवरेट स्कूल क्विज को मिस ना करें। उम्मीद है कि इस बार पार्टिसिपेंट्स की संख्या पहले से काफी ज्यादा होगी। डिस्कवरी साउथ एशिया मैनेजिंग डायरेक्टर मेघा टाटा बताती हैं कि सिर्फ दो साल में डीएसएसएल इंडिया का फेवरिट स्कूल क्विज बनकर उभरा है। विजेता टीम को नासा की मुफ्त यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। सभी प्रतिभागियों को 2 माह का मुफ्त बायजूस ट्यूटोरियल पैकेज मिलेगा।

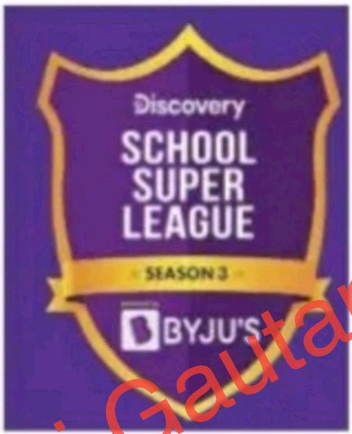

Badri Gautam

8 से 16 उम्र के छात्रों के लिए

क्विज के लिए एज ग्रुप 8 से 16 साल रखा गया है। हर प्रतिभागी को चार प्रारंभिक टेस्ट देने का मौका मिलेगा, इसके बाद स्टूडेंट्स मुख्य स्कूल क्विज में भाग लेंगे। इसके लिए एंट्री फीस नहीं है। सलेक्शन के बाद हर एक स्टेट से टॉप टीम चुनी जाएगी। वो टीम सिक्स एपिसोड टीवी क्विज शो में भाग लेगी, ये शो डिस्कवरी और डिस्कवरी किड्स चैनल पर प्रसारित होगा।

स्टूडेंट्स एंड्रॉयड और iOS पर onelink.to/3fdzvw पर उपलब्ध ऐप को डाउनलोड करके DSSL 2020 में भाग ले सकते हैं। आज ही अपने बच्चों को दुनिया की सबसे बड़ी क्विज में शामिल होकर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें।

डीएसएसएल में भाग ले रहे प्रतिष्ठित स्कूल

भोपाल-कार्मल कावेंट स्कूल	सतना-बोनांजा कावेंट स्कूल	रीवा-केंद्रीय विद्यालय
भोपाल-सेंट जेवियर स्कूल	सतना-बिरला विकास स्कूल	रीवा-बाल भारती स्कूल
भोपाल-क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल	सतना-डीपीएस स्कूल	रीवा-गीता ज्योति स्कूल
भोपाल-सेंट पॉल स्कूल	सतना-सेंट माइकल स्कूल	रीवा-ज्ञानस्थली विद्यालय
सतना-क्राइस्ट ज्योति स्कूल	रीवा-महाराजा पब्लिक स्कूल	रीवा-एमवीएम स्कूल
		रीवा-स्केयरड हार्ट स्कूल

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें- +91-9893632861

छात्रों को फेल करने के नियमों में ढील दें राज्य : शिक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली। शिक्षा मंत्रालय ने इस साल बच्चों को फेल करने के नियमों में ढील देने की सिफारिश की है। यह सिफारिश महामारी के दौरान प्रभावित हुए प्रवासी बच्चों की पहचान करने, प्रवेश देने और शिक्षा जारी रखने के उद्देश्य से की गई है। राज्यों को सलाह दी गई है कि 6 से 18 साल उम्र के उन बच्चों की पहचान के लिए घर-घर सर्वेक्षण करें, जो स्कूलों से दूर हैं। इनका स्कूलों में पंजीकरण कराने के लिए उचित कार्ययोजना तैयार की जाए।

मंत्रालय ने छात्रों को स्कूल बंद रहने के दौरान और दोबारा खुलने के बाद पहुंचाई जाने वाली मदद संबंधी दिशा- निर्देश जारी किए हैं। छात्रों की मदद के लिए चलते-फिरते स्कूल, छोटे-छोटे समूहों में कक्षाओं का संचालन, डिजिटल स्त्रोतों की पहुंच बढ़ाने पर काम करने के निर्देश दिए हैं।

Badri Gautam

अब साइकिल वितरण बंद कर स्टूडेंट्स को बस से स्कूल भेजेगी प्रदेश सरकार

सीएम राइज स्कूलों में खर्च होंगे साइकिल खरीद के 300 करोड़ रुपए

रामचन्द्र पाण्डेय ● भोपाल

मो.नं. 9893231237

पीपुल्स समाचार स्पेशल

Badri Gautam

सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को दी जाने वाली साइकिल योजना को बंद करने पर विचार किया जा रहा है। साइकिल पर खर्च होने वाला 300 करोड़ का बजट सीएम राइज योजना के तहत अपडेट होने वाले स्कूलों पर खर्च होगा। इन स्कूलों में बच्चों को लाने-ले जाने के लिए सरकार बस चलाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस तरह का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। हालांकि अधिकारी इस बारे अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। ज्ञात हो सरकारी स्कूलों के 5.91 लाख बच्चों को साइकिल वितरण किया जाता है। पहले चरण में बस की सुविधा केवल सीएम राइज स्कूल के छात्र-छात्राओं को देने की तैयारी की जा रही है। शेष स्कूल के बच्चों को फिलहाल साइकिल ही मिलेगी। यदि प्रयोग सफल हुआ तो अन्य स्कूलों में बस सुविधा लागू कर साइकिल योजना पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के एक लाख दो हजार सरकारी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है।

फैक्ट फाइल

- प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों की संख्या : 1,42,512
- हाईस्कूल व हायर सेकंडरी स्कूलों की संख्या : 6,534
- साइकिल वितरण के लिए छात्राओं की संख्या : 5,91,406

बंद नहीं होगा साइकिल वितरण

सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम राइज योजना भी शामिल है। अभी फिलहाल साइकिल वितरण योजना को बंद करने की कोई प्लानिंग नहीं है।

–रश्मि अरुण शमी, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग

महिलाओं ने रैली निकालकर मांगी पुरानी पेंशन

Badri Gautam

जागरण, रीवा। पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग को लेकर महिलाओं ने रविवार को रैली निकाली और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग करते हुए कहा कि जनवरी 2005 से पेंशन बंद है, जो उचित नहीं है। ज्ञात हो रविवार को शहर के विवेकानंद पार्क में संभागीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सतेन्द्र सिंह तिवारी प्रांताध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि संध्या पाण्डेय तथा कार्यक्रम का संचालन संभागीय अध्यक्ष मीना दुबे ने किया। आभार प्रदर्शन निर्मला द्विवेदी ने किया। महिलाओं ने कहा कि नवीन पेंशन योजना हमारे लिए घातक है। इसके खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के साथ महिलायें कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगी। कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यह समझ लेना चाहिए कि उनकी बहनें पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आई हैं। ऐसे में यदि वह सचमुच में अपने को भाई कहते हैं तो उन्हें हम महिलाओं के सम्मान में इस समस्या का हल करना चाहिए। अन्यथा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी उसके लिए यहां से लेकर भोपाल तक संघर्ष किया जायेगा। इस अवसर पर प्रमुख रूप से सतना जिला अध्यक्ष आकांक्षा पाण्डेय, अंकिता शुक्ला रीवा, गीता शुक्ला रीवा, ज्योत्सना सिंह, मीना राल्ही, निशा पटेल, कृष्णा तिवारी, विभा त्रिपाठी, सावित्री पटेल, उमा पाण्डेय, रेखा कोल, विजय लक्ष्मी पटेल, संध्या सोनी, सीता वर्मा सहित सैकड़ों महिलायें उपस्थित रहीं।

विद्यार्थियों का पंजीकरण व फेल करने ....

कोविड–19 महामारी की वजह से हमारे स्कूली बच्चों के समक्ष उत्पन्न चुनौती को कम करने के लिए यह महसूस किया गया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ड्रॉपआउट बढ़ने एवं पंजीकरण कम होने, पढ़ाई के नुकसान, हाल के वर्षों में सार्वभौमिक एवं गुणवत्तापरक जो शिक्षा मुहैया कराई गई है, उसमें कमी की समस्या से निपटने के लिए उचित नीति बनाने की जरूरत है। अधिकारी ने कहा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि छह से 18 साल उम्र के उन बच्चों की पहचान के लिए घर–घर सघन सर्वेक्षण किया जाए जो स्कूलों से दूर हैं, साथ ही उनका स्कूलों में पंजीकरण कराने के लिए उचित कार्ययोजना तैयार की जाए। मंत्रालय ने विद्यार्थियों को स्कूल बंद होने के दौरान और दोबारा उनके खुलने के बाद पहुंचाई जाने वाली मदद संबंधी दिशनिर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि स्कूलों के बंद रहने के दौरान विद्यार्थियों की मदद करने के लिए चलते–फिरते स्कूल, गांवों में छोटे–छोटे समूह में कक्षाओं का संचालन, बच्चों तक ऑनलाइन एवं डिजिटल स्रोतों की पहुंच बढ़ाने, पढ़ाई का नुकसान कम करने के लिए टेलीविजन एवं रेडियो के जरिए पढाई की संभावनाओं पर गौर करने की सिफारिश की गई है।

Badri Gautam

विद्यार्थियों का पंजीकरण व फेल करने के नियमों में ढील की सिफारिश

नई दिल्ली, भाषा। शिक्षा मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के असर को कम करने के प्रयास के तहत राज्यों से घर-घर जाकर स्कूल जाने वाले बच्चों का सर्वेक्षण करने और उनका स्कूलों में पंजीकरण कराने की योजना बनाने की सिफारिश की है। अधिकारियों ने बताया कि मंत्रालय ने इस साल बच्चों को फेल (अनुत्तीर्ण) करने के नियमों में भी ढील देने की सिफारिश की है। उन्होंने बताया कि यह सिफारिश महामारी के दौरान प्रभावित हुए प्रवासी बच्चों की पहचान करने, प्रवेश देने और शिक्षा जारी रखने के उद्देश्य से की गई है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ▪ शेष पृष्ठ 9 पर

Badri Gautam

फर्जी पीएचडी के सहारे हासिल की नौकरी

उच्च शिक्षा ने तीन शिक्षकों पर बैठाई विभागीय जांच, एडी रीवा को दी जिम्मेदारी

जागरण, रीवा

उच्च शिक्षा के महकमे में फर्जी डिग्री के सहारे नौकरी हथियाने के चर्चे अक्सर होते रहे। इस सिलसिले में फर्जी पीएचडी डिग्री लेकर नौकरी की शिकायत उच्च शिक्षा के शीर्ष अधिकारियों से हुई है। शिकायत में विभाग के तीन नियमित शिक्षकों की पीएचडी डिग्री को फर्जी बताया गया है। मामले को गम्भीरता से लेते हुए विभाग ने अब संबंधित शिक्षकों पर विभागीय जांच बैठा दी है और जांच अधिकारी विभाग ने एडी रीवा को नियुक्त किया है। विभाग ने एडी रीवा से मामले की जांच कर रिपोर्ट शीघ्र मांगी है। ताकि आगामी कार्यवाही विभाग द्वारा की जा सके। विभाग की उपसचिव श्वेता पवार ने इस बाबत गत 2 जनवरी को आदेश जारी किए हैं।

मामले में बताते हैं कि छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर के कुलसचिव डॉ पीके पटेरिया मूलतः रसायनशास्त्र विषय के सहायक प्राध्यापक हैं, जिनकी पीएचडी डिग्री को लेकर शिकायत दी गई है। इसी प्रकार छतरपुर के ही शासकीय महाविद्यालय नौगांव के भौतिक विभाग में पदस्थ डॉ धर्मेश खरे की पीएचडी डिग्री को लेकर भी शिकायत में आपत्ति दर्ज कराई गई है। इसके अलावा ग्वालियर डबरा के सरकारी महाविद्यालय के वनस्पतिशास्त्र के शिक्षक डॉ विशाल कदम की पीएचडी डिग्री पर प्रश्नचिन्ह लगाया गया है।

जोधपुर नेशनल विवि से ली डिग्री

बताते हैं कि उक्त तीनों ही नियमित शिक्षकों ने राजस्थान के जोधपुर नेशनल विश्वविद्यालय से यह पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। शिकायत के बाद शुरूआती जांच में विभाग को मामले को लेकर कुछ शंका हुई और संबंधितों से भी संतोषजनक उत्तर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं मिला। लिहाजा विभाग ने अब विभागीय जांच कराने का निर्णय लिया है। इस जांच में यदि शिकायत सही पाई जाती है तो उक्त तीनों शिक्षकों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई हो सकती है।

रीवा विवि में भी कट रही मौज

गौरतलब है कि देश-प्रदेश समेत रीवा जिले में भी बेरोजगारों की भरमार है। इसके बावजूद कुछ घूसखोर अधिकारियों की बदौलत इस तरह की फर्जी डिग्री और नियुक्ति लिये लोग मौज काट रहे हैं। रीवा विश्वविद्यालय में भी एक सिस्टम इंचार्ज को उपकृत करने तमाम आला अधिकारी लगे हुए हैं। पहले भी रीवा विश्वविद्यालय के कुछ नियमित शिक्षकों को नियम विरूद्ध आचार्य पद प्राप्त हो चुका है, इनमें से कई अब भी कार्यरत हैं। शासन-प्रशासन के जिम्मेदार उपकृत हुए लोगों से अपना हिस्सा लेकर चुप हैं।

Badri Gautam

NLU की प्रवेश परीक्षा अब 20 जून को होगी

भोपाल। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट की तारीखों में बदलाव कर दिया है। जिसकी वजह से अब एंट्रेंस एग्जाम 20 जून को आयोजित होगा। इससे पहले यह एग्जाम 2 मई को आयोजित किया जाना था। इस संबंध में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी कर दी है। वहीं क्लेट परीक्षा 13 जून को आयोजित होगी। देशभर के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और कॉलेज में में एडमिशन के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लेट) आयोजित किया जाता है। इस परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों को 5 वर्षीय लॉ कोर्स में एडमिशन दिया जाता है। यह परीक्षा हर वर्ष आयोजित की जाती है, जिसमें देशभर से लाखों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं।

Badri Gautam

कोरोना संक्रमण की स्थिति ठीक होने के बाद विश्वविद्यालय का दौरा करेगी नैक की टीम

बीयू: ए प्लस तो दूर, अब 'बी' ग्रेड बचाना भी मुश्किल

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल
मो.नं. 9893231237

नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल (नैक) से अच्छी ग्रेड पाने की तैयारियों में प्रदेश के विश्वविद्यालय जुटे हुए हैं, लेकिन बीयू सहित अन्य विश्वविद्यालयों के सामने फैकल्टी की कमी नैक की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है।

नैक के दौरे से पहले बीयू में कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी रखी जानी थी, लेकिन कोरोना के कारण यह व्यवस्था भी नहीं हो सकी है। वर्तमान में बीयू में 50 फीसदी नियमित शिक्षक हैं। इनमें से 3 प्रोफेसर 2021 में रिटायर हो जाएंगे। मौजूदा फैकल्टी के भरोसे ए प्लस तो दूर, बी ग्रेड भी बचाना

मुश्किल है। बीयू, जीवाजी, विक्रम और देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी की नैक एक्रीडिएशन की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। इनमें से कुछ ने नैक के लिए आवेदन कर दिया है। वहीं, कुछ विवि मापदंड पूरा नहीं करने के कारण आवेदन भी नहीं कर पा रहे हैं। बीयू की स्थिति और भी खराब है। नैक की टीम ने मार्च 2015 में बीयू का दौरा किया था। तब जो कमियां मिली थीं, नैक ने उनकी रिपोर्ट बनाकर बीयू को भेज दी थी। रिपोर्ट मिलने के बावजूद बीयू प्रशासन ने कमियों को दूर करने के लिए कदम नहीं उठाए। मार्च 2020 में यह अवधि समाप्त हो गई है। बीयू ने नैक के लिए आवेदन तो कर दिया है, लेकिन वर्तमान में 85 पदों पर मात्र 40 नियमित शिक्षक हैं। इनमें तीन तो साल के अंत तक रिटायर हो जाएंगे।

बीयू आवेदन की स्थिति में नहीं

विश्वविद्यालयों को पांच साल के लिए नैक सर्टिफिकेट मिलता है। नैक ने जुलाई 2016 में निरीक्षण को लेकर नियमों में संशोधन किया था। इसके तहत एक्रीडिएशन खत्म होने से छह महीने पहले आवेदन करना अनिवार्य किया गया। मगर दिसंबर 2018 में नैक ने नया आदेश जारी किया, इसमें शैक्षणिक संस्था एक्रीडिएशन की समयावधि खत्म होने से सप्ताहभर पहले भी आवेदन कर सकती है। नए आदेश ने विवि को राहत दी है। फिर भी बीयू आवेदन की स्थिति में नहीं है।

सभी मापदंड पूरा कर लेंगे

" बीयू में नैक की साइकिल समाप्त हो चुकी है। हम आवेदन करने के साथ नैक की अगली साइकिल की तैयारी कर रहे हैं। टीम के निरीक्षण तक सभी मापदंडों को पूरा कर लिया जाएगा।

अजीत कुमार, रजिस्ट्रार, बीयू

Badri Gautam

सभी कॉलेजों में आज से नियमित लगेंगी यूजी और पीजी की कक्षाएं

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल

मो.नं. 9893231237

मप्र के सरकारी और प्राइवेट कॉलेज एक जनवरी से खुल चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकल कक्षाएं ही लग रही थीं। सोमवार से कॉलेज में कक्षाएं लगना शुरू हो जाएंगी। पहले 10 दिन तक प्रैक्टिकल कक्षाएं लगाने के बाद अगले दस दिनों तक नियमित कक्षाओं का संचालन होगा। यह एक ट्रायल रन की तरह होगा।

इन 10 दिनों में जो कक्षाएं लगाई जाएंगी, उसको लेकर 20 जनवरी को सभी जिलों के आपदा प्रबंधन की बैठक होगी। उसके बाद कॉलेज को आगे नियमित खोलने और क्लास की संख्या बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा। तीन चरणों में कॉलेज में क्लासेस शुरू की जा रही हैं। 1 से 10 जनवरी तक प्रैक्टिकल क्लासेस, 10 जनवरी से स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर की कक्षाएं तथा 20 से शेष कक्षाएं प्रारंभ की जाएंगी।

ऑनलाइन कक्षाएं रहेंगी चालू: गाइडलाइन के अनुसार कॉलेज संचालक स्टूडेंट्स को कॉलेज आने के लिए दबाव नहीं डाल सकेंगे। जब तक पैरेंट्स की लिखित परमिशन नहीं होगी, स्टूडेंट्स की रेगुलर क्लास में अटेंडेंस नहीं ली जा सकती है। स्टूडेंट्स की एक तिहाई उपस्थिति से कक्षाएं लगेंगी। स्टूडेंट कॉलेज नहीं आना चाहते हैं, तो पहले की तरह ऑनलाइन क्लास चालू रहेंगी।

Badri Gautam

विलोपित नहीं हो पाए पिछड़ा वर्ग सूची से केवट, ढीमर, मल्लाह और कहार

भोपाल(आरएनएन)। मध्यप्रदेश में माझी जनजाति के पर्याय माने जाने वाले माझी ढीमर मल्लाह कहार को राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग की सूची के क्रमांक 12 से विलोपित नहीं कर पाई है। अब इस मामले में इस जनजाति के समर्पित लोग आगे आए हैं।

इनके द्वारा बताया गया कि संवैधानिक रूप से 7 जनवरी 1950 में माझी जनजाति के पर्याय केवट, मल्लाह, भोई ढीमर को जनजाति माना हैं। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति की सूची क्रमांक 29 पर अंकित माझी जनजाति हैं। तत्समय 1984 को मप्र सरकार ने 26 दिसंबर 1984 में अनुसूचित रूप से पिछड़ा वर्ग सूची क्र. 12 पर माझी केवट मल्लाह भोई ढीमर को असंवैधानिक रूप से शामिल कर आदिवासी हितों से समुदाय को वंचित किया गया। माझी जनजाति समुदाय की लगातार न्यायोचित मांग के बाद वर्ष 1992 में सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग सूची क्रमांक 12 पर से माझी विलोपित किया गया है। शेष भाग केवट मल्लाह भोई ढीमर को विलोपित नही किया। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मंत्री परिषद निर्णय के मुताबिक 25 जून 2003 में ढीमर भोई कहार मल्लाह केवट आदि को विलोपित करने के निर्णय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई । माझी जनजाति सामाजिक विकास कल्याण समिति के अध्यक्ष राकेश कुमार के अनुसार इस मामले में सरकार द्वारा पारदर्शी निर्णय करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा गठित अध्ययन समिति के निर्णय 06अगस्त. 2018 एवं आदिम जाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश का पत्र दिनांक 18 दिसंबर 2018 कुछ अलग ही बात परिभाषित कर रहा है। इसके अनुसार मध्यप्रदेश माझी जनजाति के पर्याय केवट मल्लाह भोई ढीमर कहार को न्यायोजित संवैधानिक रूप से परिभाषित मान्य कर पिछड़ा वर्ग सूची क्रमांक 12 से माझी जनजाति के पर्याय केवट मल्लाह भोई ढीमर कहार विलोपित करने की अनुशंसा के बाद कार्रवाई लंबित हैं । जबकि मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग सूची क्रमांक 58 पर अंकित खेरवा जाति को खेरवार अनुसूचित जनजाति पर्याय मान्य कर दिनांक 9 अगस्त 2018 को विलोपित किया गया है।

चुनाव से पहले मौजूदा मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सिंधिया ने दिया था भरोसा

Badri Gautam

विधानसभा उपचुनाव के पहले मिला था भरोसा

राकेश कुमार के अनुसार विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, ओपी भदौरिया मंत्री, प्रद्युमन सिंह तोमर, रामखेलवान पटेल मंत्री, मोहन यादव मंत्री एवं अन्य विधायकों के द्वारा कहा गया था कि हमारी बहुमत वाली सरकार बनते ही पिछड़ा वर्ग सूची क्रमांक 12 पर अंकित पर्याय केवट मल्लाह भोई ढीमर कहार को विलोपित के आदेश जारी किए जाएंगे। किंतु सरकार के द्वारा विलोपित के आदेश जारी नहीं होने के कारण संपूर्ण मध्यप्रदेश के माझी जनजाति समुदाय में रोष व्याप्त है। मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव के पूर्व पिछड़ा वर्ग सूची क्रमांक 12 पर अंकित माझी जनजाति के पर्याय केवट मल्लाह भोई ढीमर कहार को विलोपित के आदेश जारी किए जाएं।

वेतन विसंगति को लेकर व्याख्याता, प्राचार्य संवर्ग ने बनाई रणनीति

अमरजीत मैरिज गार्डन में हुई बैठक, सरकार को घेरने की तैयारी

जागरण, रीवा। स्कूल प्राचार्य और व्याख्याताओं ने सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। वेतन विंगति सहित सहायक संचालक के पद पर सीधी भर्ती का भी विरोध किया गया है। प्राचार्य और व्याख्याताओं ने विसंगतियां दूर न होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है।

रविवार को स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता, प्राचार्य संवर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। समग्र व्याख्याता एवं प्राचार्य कल्याण मंच के बैनर तले अमरजीत मैरिज गार्डन में सोशल डिस्टेंसिग के साथ की गई। बैठक में इस संवर्ग की पदोन्नति एवं वेतन विसंगति को लेकर चर्चा की गई। संवर्ग के वरिष्ठ अधिकारियों ने 1989 के बाद से वेतन एवं पदोन्नति में आई क्रमशः विसंगतियों को रेखांकित किया। इसमें तृतीय समयमान वेतनमान में 7600 का ग्रेड पे प्रमुख मांग थी। साथ ही सहायक संचालक के पद पर सीधी भर्ती के लिए योग्यता स्नातक रखे जाने का भी विरोध किया गया। 1966 के भर्ती एवं पदोन्नति अधिनियम में सहायक संचालक पद की योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक प्रशिक्षण एवं 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव का उल्लेख है। सहायक संचालक पद पर सीधी भर्ती का विरोध करने का निर्णय लिया गया। बैठक में प्राचार्य संवर्ग के हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी के लिए अलग-अलग पदों की व्यवस्था पर भी विरोध दर्ज कराया गया। बैठक को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंच के प्रांतीय अध्यक्ष मुकेश शर्मा सहित डॉ प्रेम लाल मिश्रा, डॉ मिथिलेश सिंह, राजेंद्र सिंह, डॉ लाख नारायण पांडे, मनमोहन वर्मा , एसके दुबे एवं आरएस पटेल ने संबोधित किया। अंत में आभार प्रदर्शन आरपी भूर्तिया ने किया। बैठक में संवर्ग के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

Badri Gautam

नया कारनामा: गूगल पर पब्लिक हो चुकी हैं ढेरों वॉट्सऐप ग्रुप चैट लिंक

कोई भी सर्च कर इसमें जुड़ सकता है, प्रोफाइल पर भी खतरा

नई दिल्ली, जेएनएन

वॉट्सऐप प्राइवेसी से जुड़ा एक नया मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉट्सऐप ग्रुप की लिंक अब दोबारा गूगल सर्च रिजल्ट पर दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ गूगल पर सर्च करके प्राइवेट वॉट्सऐप ग्रुप को ढूंढ सकता है और उसमें शामिल हो सकता है। इससे पहले 2019 में भी यह सामने आया था, जिसके बाद कंपनी ने इसे खामी को ठीक कर दिया था। एक और पुराना मुद्दा जिसे पहले फिक्स किया जा चुका है, वो भी सामने आ रहा है, जिसमें वॉट्सऐप प्रोफाइल अब सर्च रिजल्ट पर दिखाई दे रही हैं। इस खामी के कारण लोगों के फोन नंबर और प्रोफाइल फोटो सिर्फ एक साधारण गूगल सर्च से सामने आ सकते हैं।

Badri Gautam

2019 में सामने आया था ऐसा ही मामला

यह पहली बार नहीं है कि जब इस तरह की खामी सामने आई है। नवंबर 2019 में, वॉट्सऐप ग्रुप चैट इनवाइट गूगल सर्च रिजल्ट पर पाए गए थे। एक सिक्योरिटी रिसर्चर ने इस मुद्दे को फेसबुक को बताया था, हालांकि मामला सुर्खियों में आने के बाद कंपनी ने इसे तुरंत ठीक भी कर दिया था। रिवर्स इंजीनियर जेन मानचुन वोंग ने बताया कि वॉट्सऐप ने चैट इनवाइट लिंक पर 'नो-इंडेक्स' मेटा टैग जोड़कर ग्रुप चैट इंडेक्स को फिक्स किया था।

फोन नंबर और प्रोफाइल फोटो भी कर सकते हैं एक्सेस

ग्रुप चैट इनवाइट्स की इंडेक्सिंग की अनुमति देकर, वॉट्सऐप अब वेब पर कई प्राइवेट ग्रुप उपलब्ध करा रहा है, क्योंकि उनके लिंक गूगल पर एक सिंपल सर्च क्वेरी का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकते हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जिसे भी यह लिंक मिलती है, वो ग्रुप में न सिर्फ शामिल हो सकते हैं बल्कि मेंबर्स और द्वारा ग्रुप में शेयर किए जा रहे हैं। पोस्ट के साथ उनके फोन नंबर भी देख सकते हैं।

कुछ ग्रुप पोर्न शेयर करने वाले थे

साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर राजशेखर राजाहारिया ने गूगल पर वॉट्सऐप ग्रुप चैट इनवाइट के इंडेक्सिंग की जानकारी दी। खबर लिखते समय तक, सर्च रिजल्ट्स में लगभग 1,500 से अधिक ग्रुप इनवाइट लिंक उपलब्ध थे। गूगल द्वारा इंडेक्स की गई कुछ लिंक पोर्न शेयर करने वाले वॉट्सऐप ग्रुप को लीड करते हैं। कुछ अन्य मामलों में, कुछ खास समुदाय या इंटरेस्ट वाले वॉट्सऐप ग्रुप्स के लिंक थे। इसके अलावा बंगला और मराठी यूजर्स के लिए मैसेज शेयर करने वाले ग्रुप्स मिले। इस लिंक के साथ, जिन लोगों को इनवाइट नहीं किया गया था, वे भी आसानी से ग्रुप्स में शामिल हो सकते हैं।

ग्रुप चैट इंडेक्सिंग की तरह गूगल सर्च इंजन पर लगभग 5000 प्रोफाइल दे रही हैं दिखाई

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ग्रुप चैट इंडेक्सिंग की तरह वॉट्सऐप यूजर्स की प्रोफाइल भी पिछले कुछ घंटों से गूगल पर फिर से उपलब्ध हैं। सर्च इंजन पहले से ही 5,000 प्रोफाइल लिंक पर इंडेक्स है। राजाहारिया ने गूगल पर वॉट्सऐप यूजर्स प्रोफाइल की इंडेक्सिंग की खोज की। उन्होंने देखा कि जैसा ग्रुप चैट इनवाइट में देखा गया था, प्रोफाइल के मामले में वैसा कोई api.whatsapp.com सबडोमेन के लिए कोई विशेष robots.t&t फाइल नहीं है, जो सर्च इंजन क्रॉलर को अपने संबंधित लिंक क्रॉल नहीं करने के लिए कहता है। ग्रुप चैट इनवाइट लिंक के साथ लगता है कि वॉट्सऐप ने गूगल को फिर से यूजर्स की प्रोफाइल इंडेक्स करने की अनुमति दी है, जिससे कोई भी यूजर्स के साथ चैट कर सके या उसकी प्रोफाइल फोटो देख सके। वॉट्सऐप के डोमेन पर कंट्री कोड की खोज करके, लोगों के प्रोफाइल के यूआरएल सामने आ सकते हैं, जिसमें फोन नंबर और प्रोफाइल फोटो शामिल थे। यह मुद्दा पिछले साल जून में वॉट्सऐप द्वारा फिक्स किया गया था।

प्रभार देने पर चल रहा विचार

साढ़े 4 लाख कर्मचारियों की पदोन्नति का विकल्प तलाशने बैठक कल

शिवराज सरकार की बनाई समिति की तीन बैठक हो चुकी है संपन्न, पंद्रह तक देना है रिपोर्ट

शहर प्रतिनिधि, भोपाल। शिवराज सरकार द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति का विकल्प तलाशने के लिए बनाई समिति की 12 जनवरी को महानिदेशक प्रशासन अकादमी एपी श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आखिरी बैठक होगी। समिति वर्तमान कानूनी परिस्थिति को ध्यान में रखकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उच्च पदों का प्रभार देने की नीति तैयार करने पर मंथन कर रही है। समिति की तीन बैठक हो चुकी है। सरकार ने समिति से हर हाल में 15 जनवरी तक अनुशंसाएं मांगी हैं।

प्रदेश में करीब साढ़े चार साल से पदोन्नति पर लगी रोक के चलते राज्य सरकार को कर्मचारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। पदोन्नति की मांग को लेकर कर्मचारी आए दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विभिन्न विभागों के मंत्रियों से मिल रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने नौ दिन पहले प्रशासन अकादमी के महानिदेशक एपी श्रीवास्तव की अध्यक्षता में समिति गठित की है। समिति प्रदेश में पदोन्नति पर रोक के कानूनी पहलुओं का अध्ययन कर कर्मचारियों को उच्च पदों का प्रभार देने की नीति तैयार कर रही है। समिति में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन सदस्य सचिव है। जबकि अपर मुख्य सचिव जल संसाधन, गृह एवं जेल,

प्रमुख सचिव राजस्व व लोक सेवा प्रबंधन और विधि एवं विधायी कार्य विभाग सदस्य हैं। पदोन्नति का विकल्प तलाशने के लिए बनाई समिति की दो से तीन बैठक महानिदेशक प्रशासन अकादमी एपी श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपन्न हो चुकी है। समिति 12 जनवरी को वर्तमान कानूनी परिस्थिति को ध्यान में रखकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उच्च पदों का प्रभार देने की नीति को अंतिम रूप देगी। सरकार ने समिति से हर हाल में 15 जनवरी 2021 तक अनुशंसाएं मांगी हैं।

पदनाम देने से सरकार पर नहीं आएगा आर्थिक बोझ

अधिकारी-कर्मचारियों को प्रमोशन न मिलने की स्थिति में उच्च पद का प्रभार देकर पदनाम दिए जाने से सरकार पर आर्थिक बोझ नहीं आएगा। इसकी वजह कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ मिलने से पहले ही उच्च पदों का वेतनमान मिल रहा है।

साढ़े चार साल से नहीं मिली पदोन्नति

मप्र लोक सेवा (पदोन्नति) अधिनियम 2002 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर ने 30 अप्रैल 2016 को खारिज कर दिया था। इस कानून में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्थगन मांगा था, पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी होने से हाई कोर्ट के फैसले पर यथास्थिति रखने के निर्देश दिए हैं। तभी से प्रदेश में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक है। इस अवधि में 65 हजार से ज्यादा कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं। इनमें से करीब 30 हजार ऐसे भी कर्मचारी थे, जो पदोन्नति मिले बगैर ही सेवानिवृत्त हो गए।

Badri Gautam

जारी है बेगारी **दैनिक वेतन भोगियों चतुर्थ श्रेणी की पदस्थापना कार्यालयों में, काम बंगलों पर**

सामान्य प्रशासन का आदेश, आला अफसरों ने नहीं माना कोई निर्देश

वर्ष 1996 में सामान्य प्रशासन विभाग ने बेगारी प्रथा समाप्त करने जारी किया था आदेश

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

प्रदेश में अल्प वेतन पाने वाले निचली श्रेणी कर्मचारियों के प्रति अफसरों में जरा भी संवेदनाएं नहीं दिख रही हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के भी आदेश है कि इन कर्मचारियों से बंगलों पर बेगारी का काम ना करवाया जाए। उसके बाद भी कई सालों से ऐसे कर्मचारी दफ्तरों में फाइलें उठाने की बजाय अफसरों के यहां भोजन पकाने, झाड़ू लगाने और कुत्ता घुमाने जैसे काम कर रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के विभाग के अपर सचिव ऐसी पंड्या द्वारा 10 सितंबर 1996 को एक आदेश जारी किया गया था। इस आदेश में सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया था। इसमें स्पष्ट उल्लेख था कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी एवं स्थाई कर्मियों से बंगलों में घरेलू कार्य न कराए जाएं। कार्यालय में पदस्थापना है। इस कारण नियम को ध्यान में रखते हुए यथा स्थान पर ही इनसे कार्य लिया जाए। इसी तारतम्य शासन द्वारा कई बार आदेश जारी किए गए। इसके बावजूद भी आज स्थिति यह है की एक भी विभाग द्वारा इसका पालन नहीं कियाा गया है। लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, वन विभाग, जल संसाधन विभाग, आदिम जाति कल्याण, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, कृषि, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा खाद्य एवं औषधि सहित अनेक विभागों में इन कर्मचारियों से अधिकारी अपने बंगलों पर काम ले रहे हैं।

राजधानी के हाल: भोपाल में देखा जाए या फिर जिला संभाग मुख्यालयों पर पदस्थ अधिकारियों के बंगले हो। सभी जगहों पर बेगारी में इन कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। ऐसा एक भी बांग्ला नहीं मिलेगा जिनमें चतुर्थ श्रेणी दैनिक वेतन भोगी स्थाई कर्मी ना मिले। इन बंगलों में स्थाई कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के द्वारा चूल्हा चौका, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, कुत्ता घुमाने जैसे कार्यों का संपादन किया जाता है।

कई अधिकारी के बंगले पर बेगारी का कार्य

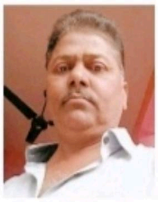

मध्यप्रदेश स्थाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शारदा सिंह परिहार का कहना है कि प्रत्येक अधिकारियों के बंगले में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी की संख्या 5 से लेकर 10 तक है। यदि उक्त कर्मचारी इन कार्यों को करने से मना करता है तो निश्चित रूप से उसकी नौकरी खतरे में है। यहां तक की मैडम का फोन आना स्वाभाविक है कि उक्त कर्मचारी की तनख्वाह न दी जाए। ऐसी हालातों में आज इन कर्मचारियों की स्थिति बद से बदतर है।

वे नहीं चाहते कर्मचारी समाज की मुख्यधारा से जुड़ें

स्थाई कर्मचारी संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी अशोक पाटिल का कहना है कि अधिकारी चाहते ही नहीं है कि यह अल्प बेतन भोगी कर्मी समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें। जिसका प्रमुख कारण नौकरशाही है। क्योंकि यदि मुख्यमंत्री के आदेश पर स्थाई कर्मियों को नियमित कर दिया जाएगा तो फिर उनके बंगलों पर चूल्हा चौका का काम कौन करेगा। इसी सोच के चलते आज आजाद देश के गुलाम नागरिकों की तरह हम अल्प वेतन भोगी कर्मचारी जीवन जीने के लिए मजबूर है।

कई बार लिखा शासन को पत्र

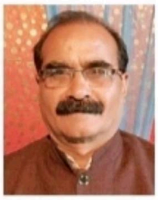

मध्यप्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र शर्मा का कहना है कि इस बेगारी से मुक्ति दिलाने के लिए कई बार शासन को पत्र लिखा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी विभाग अध्यक्षों को भी इस पत्र की प्रति जाती है लेकिन इसका पालन आज तक नहीं किया गया है। आने वाले आंदोलनों में यह मुद्दा प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा।

बंगलों पर बेगारी प्रथा समाप्त होना चाहिए: जाट

लघु वेतन कर्मचारी संघ के संरक्षक निहाल सिंह जाट का कहना है कि अधिकारियों के बंगलों पर दैनिक वेतन भोगियों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों कि जो ड्यूटी लगी हुई है पूरी तरह गलत है। क्योंकि इनकी पदस्थापना कार्यालयों में है। इस कारण इनसे काम भी दफ्तर में ही लेना चाहिए। कई कर्मचारी तो ऐसे ही जिन्होंने आज तक अपनी पदस्थापना के बाद से कार्यालय में कोई फाइल ही नहीं उठाई है। यह बंगलों पर ही बेगारी में लगे हुए हैं।

Badri Gautam

राष्ट्रीय कला उत्सव 2020 का आयोजन आज से 21 जनवरी तक

भोपाल। ऑनलाइन मोड पर राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश के चयनित 18 प्रतिभागियों के साथ कला उत्सव आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी में 11 से 21 जनवरी तक संपन्न होगा। स्कूल शिक्षा विभाग और भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 से उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की कला प्रतिभा को पोषित करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष राष्ट्रीय कला उत्सव का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में यह इंगित किया गया है कि स्कूली विद्यार्थियों को भारत की जीवंत सांस्कृतिक परंपरा एवं विविधता से परिचय कराना हमारी शिक्षा नीति का व्यापक उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को समाहित कर स्कूली विद्यार्थियों के लिए कला उत्सव का आयोजन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। कला उत्सव एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कला उत्सव में प्रतिभागी विद्यार्थी अपने राज्य की कला संस्कृति एवं मूल्यों को समझते हैंए साथ ही उसे आगे बढ़ाते है। नई शिक्षा नीति 2020 में यह अंकित किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी को भारत की संस्कृति और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं दर्शन का महत्व समझाने के उद्देश्य से हमें स्कूली शिक्षा में आवश्यक सुधार करने होंगे इसी व्यापक सोच को लेकर एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय कला उत्सव का आयोजन किया जाता है। कला उत्सव में विभिन्न राज्यों के प्रतिभागियों को अन्य राज्यों की सांस्कृतिक विरासत को समझते का अवसर मिलता हैंए संस्कृति का आदान-प्रदान होता है और भारतीय संस्कृति की कला संस्कृति और विरासत को प्रोत्साहन मिलता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 11 से 21 जनवरी के मध्य कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुरूप ऑनलाइन मोड पर कला उत्सव में भाग लेंगे। मध्यप्रदेश राज्य के विभिन्न्न विधाओं में संगीत गायन, वाद्य, नृत्य शास्त्रीय लोक गायन, दृश्य कला दीवानी मूर्तिकला स्थानीय खेल खिलौने आदि विधाओं में बच्चे प्रशासन अकादमी के भोपाल स्थित स्टूडियो में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। जिसका सीधा प्रसारण सीआईईटीए एनसीईआरटी के स्टूडियो में होगा। राष्ट्रीय कला उत्सव का आयोजन आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन अकेडमी में किया गया है और दृश्य कला की प्रतियोगिताएं शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय, भोपाल में संपन्न होंगी। गत वर्ष राष्ट्रीय कला उत्सव में मप्र के प्रतिभागियों ने दृश्य कला एवं संगीत वादन में पुरस्कार प्राप्त किए थे।

Badri Gautam

वॉट्सऐप और फेसबुक के खिलाफ उतरे कारोबारी, बैन लगाने की मांग

कैट ने वॉट्सऐप की नई गोपनीयता नीति पर कड़ी आपत्ति जताई है

नई दिल्ली | एजेंसी

कारोबारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप की नई गोपनीयता नीति पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उस पर बैन लगाने की मांग की है। कैट का कहना है कि वॉट्सऐप नई नीति से ऐप को इस्तेमाल करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के सभी प्रकार के व्यक्तिगत डेटा, भुगतान लेनदेन, संपर्क, स्थान और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को हासिल कर किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद को भेजे गए एक पत्र में कैट ने मांग की है कि सरकार को वॉट्सऐप को नई गोपनीयता नीति को लागू करने से तुरंत रोकना चाहिए तथा वॉट्सऐप और उसकी मूल कंपनी फेसबुक पर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। भारत में फेसबुक के 20 करोड़ से अधिक यूजर हैं और कंपनी द्वारा प्रत्येक उपयोगकर्ता के डेटा को अपनी नीति के माध्यम से जबरन प्राप्त करने से न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।

ईस्ट इंडिया कंपनी की याद

कैट ने कहा, 'यह हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के उन दिनों की याद दिलाता है। कंपनी ने नमक का व्यापार करने के लिए भारत में प्रवेश किया और देश गुलाम हुआ लेकिन वर्तमान समय में डेटा ही अर्थव्यवस्था एवं देश की सामाजिक संरचना के लिए महत्वपूर्ण है। बिना किसी शुल्क के फेसबुक और वॉट्सऐप का उपयोग करने के लिए भारतीयों को पहले सुविधा देने के पीछे उनका असली मकसद अब सामने आ रहा है। उनका उद्देश्य प्रत्येक भारतीय के डेटा को हासिल करना है और अपने छिपे हुए एजेंडे के साथ भारत के व्यापार और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना है।

निजता नीति एक व्यक्ति की निजता का अतिक्रमण है

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा की वॉट्सऐप भारत में अगले महीने से अपनी बदली हुई निजता नीति को लागू करने वाला है जो वॉट्सऐप का उपयोग करने वाले लोगों को अपनी मनमानी और एकतरफा शर्तों को स्वीकार करने के लिए बाध्य करेगा। वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें फिर अपने मोबाइल से वॉट्सऐप को हटाना होगा। भरतिया एवं खंडेलवाल ने कहा कि वॉट्सऐप की बदली हुई निजता नीति एक व्यक्ति की निजता का अतिक्रमण है और भारत के संविधान के मूल बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। सरकार को इस मुद्दे पर तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए।

Badri Gautam

स्कूल की जमीन पर जबरन कब्जा कर किया निर्माण

फोन लगाकर प्राचार्य को दी धमकी, ऑडियो वायरल

स्टार समाचार | पन्ना

Badri Gautam

हरदुआ खमरिया हायर सेकेंडरी स्कूल तहसील रैपुरा में स्कूल की भूमि पर भवन निर्माण कराया जा रहा है। बताया जाता है कि हायर सेकेंडरी स्कूल हरदुआ खमरिया की जमीन पर पुलिस चैकी के सामने कुछ लोंगो द्वारा अबैध कब्जा कर मकान निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिस पर प्रभारी प्राचार्य द्वारा कई बार जिला प्रशासन एबं जिला शिक्षा विभाग को अबैध कब्जा करने के मामलों में आबेदन दिया गया है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जिससे स्कूल की जमीन पर अबैध कब्जा कर मकान निर्माण कार्य किया जा रहा है। कार्यवाही नहीं होने से लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। बताया जाता है कि विगत दिनों अतिक्रमणकारी को प्राचार्य द्वारा इस संबंध में शिकायत करने की जानकारी मिली तो उसने फोन कर प्राचार्य को ही जान से मारने की धमकी दे डाली। प्राचार्य ने उक्त ऑडियो रिकार्ड की जानकारी साझा की, जिसके बाद ऑडिया खासा वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण के मामलों में गंभीरता नहीं दिखाई जाती, यही कारण है कि शासन की भूमि पर लगातार कब्जा हो रहा है।

शालाओं के एकीकरण को लेकर खंड स्तरीय कार्यशाला संपन्न

बुढ़ार, (नि.प्र.)। जिला कलेक्टर डॉ. सत्येंद्र सिंह के निर्देशन पर तथा सहायक आयुक्त आ.जा.क विभाग शहडोल आर के श्रोती के मार्गदर्शन में विकास खंड शिक्षा अधिकारी सोहागपुर एस.पी.एस चंदेल की उपस्थिति में गत 8 जनवरी को जनपद शिक्षा सोहागपुर के सभागार में राज्य शासन के मापदंड अनुसार एक परिसर एक शाला (1.50 मीटर के अंतर्गत) आने वाली समस्त शालाओं को एकीकृत करने के परिणाम स्वरूप एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

शालाओं के एकीकरण की अवधारणाओं को विस्तार पूर्वक समझते हुये श्री चंदेल ने उपस्थित सभी संस्था प्रमुखों से कहा कि - प्रथम दृष्टया कर्मचारी उपस्थिति पंजी का एकीकरण तत्काल प्रभाव से हो जाना आवश्यक है इससे विषयवार शिक्षकों की प्रतिपूर्ति होगी और इसके अलावा कम संसाधनों में एक बेहतर शिक्षा प्रणाली गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा साधक नेतृत्व तथा कर्मचारी अधिकारियों सही परख बनेगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि - आपसी सामंजस्य कायम रखते हुए शासन के दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन करें कार्यशाला को शिक्षाविद के रूप में सुविदित कर्मठ विकास खंड शिक्षा अधिकारी एस पी .एस .चंदेल ने संबोधित करते हुए कहा कि - हमें शासन के मंशा अनुरुप कार्य करते हुए शिक्षा प्रणाली व्यवस्था प्रणाली की ओर अग्रसर रहकर कार्य करना चाहिए।

इस कार्यशाला में उपस्थित संस्था प्रमुखों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए इस अवसर पर विकास खंड शिक्षा अधिकारी एस.पी.एस चंदेल ने 17 जनवरी से आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सहभागी बनने की अपेक्षा सभी से की इस कार्यशाला में विकाश खंड सोहागपुर के अंतर्गत सोहागपुर एम.एल.बी शहडोल पचगावं, छतवई, कोटमा, धुरवार, खैरहा, सिंहपुर, धनपुरी, हर्रा टोला, करकटी के संकुल प्राचार्य दीपक निगम तथा अधीनस्थ संस्था प्रमुख उपस्थित रहे कार्यशाला का मंच संचालन जनपद शिक्षा केंद्र सोहागपुर के प्रभारी समन्वयक संतोष यादव ने किया।

Badri Gautam

सतना के दो कॉलेजों ने जमा की जाली रसीद

सम्बद्धता शुल्क के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी

स्टार समाचार | सतना

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्धता रखने वाले सतना जिले के दो कॉलेजों ने लाखों की धोखाधड़ी की है। विश्वविद्यालय द्वारा कारण बताओ नोटिस दिए जाने के पश्चात दोनों महाविद्यालय अब माफी मांग रहे हैं और दोष कियोस्क सेंटर संचालक पर मढ़ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि कॉलेजों द्वारा विश्वविद्यालय को सम्बद्धता शुल्क की जाली रसीद उपलब्ध कराई। इतना ही नहीं दोनों महाविद्यालयों ने जो माफीनामा भेजा, उसकी वजह भी एक ही बताई गई। ऐसे में सीकेट कन्या महाविद्यालय मैहर और सतना डिग्री कॉलेज के संचालक कठघरे के दायरे में आ जाते हैं। दरअसल मामला सम्बद्धता शुल्क से जुड़ा हुआ है।

सतना डिग्री कॉलेज द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018-19 में विश्वविद्यालय को एक लाख रुपए की कियोस्क के माध्यम से निकली रसीद जमा की। जबकि वास्तविकता में ऑनलाइन जमा शुल्क एक लाख नहीं बल्कि मात्र 10 हजार रुपए रहा। इसी प्रकार सीकेट कन्या महाविद्यालय मैहर ने भी 2 लाख 60 हजार रुपए की कियोस्क से निकली रसीद विश्वविद्यालय को सौंपी। जबकि ऑनलाइन जमा सम्बद्धता शुल्क 2 लाख 60 हजार नहीं सिर्फ 26 हजार रही। मजे की बात तो यह है कि जब विश्वविद्यालय ने दोनों कॉलेजों को कारण बताओ नोटिस भेजा तो प्राचार्य सीकेट कन्या महाविद्यालय और प्राचार्य सतना डिग्री कॉलेज का जवाब एक जैसा रहा। दोनों कॉलेजों ने ही कियोस्क सेंटर संचालक पर दोष मढ़ दिया।

विवि ने समाप्त नहीं की संबद्धता

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी हुई है। बावजूद इसके कार्रवाई सिर्फ पत्राचार तक सीमित है। शैक्षणिक सत्र 2018-19 की सम्बद्धता शुल्क अब तक अप्राप्त है बावजूद इसके कॉलेजों को मान्यता मिली हुई है। कुलपति द्वारा कारण बताओ नोटिस भेजे जाने के बाद टीप भी दी गई थी। मगर आज दिनांक तक दोनों कॉलेजों के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई और विश्वविद्यालय को शेष सम्बद्धता शुल्क भी नहीं मिली है।

प्रबंधन ने पूछा एफआईआर क्यों नहीं कराई

विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह टीप दी कि जब कियोस्क संचालक ने आपके साथ धोखाधड़ी की और सतना डिग्री कॉलेज को 90 हजार रुपए और सीकेट कन्या महाविद्यालय को 2 लाख 34 हजार रुपए का चूना लगाया, तो संस्थानों ने उक्त कियोस्क संचालक के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं की और जब दो साल बाद विश्वविद्यालय की नजर में यह सामने आया कि संबंधित महाविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता शुल्क का मात्र 10 प्रतिशत जमा किया गया है, तो इसकी जानकारी प्रबंधन को पहले क्यों नहीं दी गई।

फिलहाल मै बाहर हूं। कार्यालय पहुंचकर मैं इस मामले की बिन्दुवार जांच करूंगा और अगर ऐसी त्रुटियां सामने आती हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. राजकुमार आचार्य, कुलपति एपीएसयू

Badri Gautam

उत्कृष्ट विद्यालय के लिए बन रहा विशाल मीटिंग हाल व कम्प्यूटर लैब

विधायक के प्रयास से हो रहा निर्माण

रामपुर बाघेलान (निप्र)। शिक्षा को ही विकास का असली माध्यम मानने वाले विधायक विक्रम सिंह के प्रयास के चलते रामपुर बाघेलान के उत्कृष्ट विद्यालय में विशाल मीटिंग हाल व कम्प्यूटर लैब का निर्माण आरईएस विभाग द्वारा कराया जा रहा है । बताया जाता है कि यह कार्य विधायक रामपुर बाघेलान ने डीएमएफमद से स्वीकृत करवाया था । तकरीबन 61 लाख रुपए की लागत से दो भवनों का निर्माण किया जा रहा है जिसमें कम्प्यूटर लैब एवं तकरीबन एक हजार लोगों के बैठने के लिए भव्य मीटिंग हॉल का निर्माण आर ई एस विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही उक्त दोनों भवनो का निर्माण पूरा होगा और विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए ये उपलब्ध होंगे ।

कन्या विद्यालय को भी है भवन की जरूरत

रामपुर नगर में संचालित कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल को भी कुछ इसी तरह के भवन की जरूरत दिखाई पड़ रही है । यहाँ पर तकरीबन 9 सौ छात्राएं अध्ययन रत है । जिनके लिए मौजूदा भवन पर्याप्त नही है । सूत्र बताते हैं कि कन्या हायर सेकेंडरी में भी भवन स्वीकृत किया गया था मगर न जाने किन कारणों से निर्माण नहीं हो पाया । बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने वाली प्रदेश सरकार व रामपुर विधायक से ही लोगो ने अपेक्षा की है कि कन्या विद्यालय को भी भवन के लिए राशि स्वीकृत कराई जाय जिससे बालिकाओं को सुविधा मिल सके

इनका कहना है..

कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए बजट कुछ कारणों से स्वीकृत नहीं हो पाया था । उसमें मैं पूरी तरह से प्रयासरत हूँ और डिस्टिक माइनिंग फंड के लिए कलेक्टर की मंजूरी भी मिल चुकी है और जल्द ही बालिकाओं की शिक्षा के लिए भवन निर्माण का कार्य जल्द ही कराया जाएगा।

विक्रम सिंह
विधायक रामपुर बाघेलान

Badri Gautam

राज्य सिविल सेवा मुख्य परीक्षा-2019 के लिए आज से जमा होंगे आवेदन

भोपाल। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) राज्य सिविल सेवा मुख्य परीक्षा-2019 के लिए सोमवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेगा। जिन उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा देनी है वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पिछले महीने आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था। मुख्य परीक्षा 21 मार्च से शुरू होकर 26 मार्च तक चलेगी। परीक्षा का समय सुबह दस बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक होगा। हालांकि, निंबध का पेपर दस बजे से लेकर 12 बजे तक ही चलेगा। सारे पेपर लगातार होंगे। 21 मार्च से लेकर 24 मार्च तक चारों सामान्य अध्ययन के पेपर्स की परीक्षा ली जाएगी।

आज से कॉलेजों में शुरू होगी यूजी अंतिम वर्ष और पीजी थर्ड सेमेस्टर की कक्षाएं

भोपाल। मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेज वैसे तो एक जनवरी से अनलॉक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कॉलेजों में सिर्फ प्रैक्टिकल कक्षाएं ही लग रही थीं। आज 11 जनवरी से कॉलेज में कक्षाएं लगना शुरू हो जाएंगी। पहले दस दिनों तक सिर्फ प्रैक्टिकल कक्षाएं लगाने के बाद अब आने वाले दस दिनों तक नियमित कक्षाओं का संचालन होगा। यह एक ट्रायल रन की तरह होगा। इन 10 दिनों में जो कक्षाएं लगाई जाएंगी, उसकी 20 जनवरी को सभी जिलों के आपदा प्रबंधन की बैठक होगी। उसके बाद कॉलेज को आगे नियमित और क्लास की संख्या बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा।

Badri Gautam

यूपीएससी ने अ. प्रोफेसर और अ. डायरेक्टर के 46 पदों के लिए शुरू की भर्ती प्रक्रिया

भोपाल। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (यूपीएससी) ने असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट डायरेक्टर सहित 46 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार संघ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ऑफिशल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन मौजूद है। नोटिफिकेशन के मुताबिक आयोग की तरफ से इस भर्ती के जरिए कुल 46 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। जिसके तहत असिस्टेंट डायरेक्ट (शिपिंग), असिस्टेंट प्रोफेसर के पद शामिल हैं। भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 28 जनवरी है। इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन लिखित एग्जाम और इंटरव्यू के आधा पर किया जाएगा।

तमिलनाडुः कॉलेज छात्रों को रोजाना दो जीबी डेटा

चेन्नई। तमिलनाडु में 9.69 लाख कॉलेज छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए रोजाना दो जीबी डेटा मिलेगा। सीएम पलानीसामी ने बताया कि कोरोना के कारण ऑनलाइन क्लास में बच्चे शामिल हो सकें, इसके लिए जनवरी से अप्रैल तक मुफ्त डेटा कार्ड दिया जाएगा।

Badri Gautam

छात्रों को दाखिला देने के लिए डोर-टू-डोर सर्वे

नई दिल्ली। सभी राज्यों से शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वह डोर टू डोर सर्वे से उन बच्चों का पता करें, जो स्कूल नहीं आ रहे हैं। मंत्रालय ने यह भी सलाह दी है कि खासकर पलायन के कारण स्कूल से दूर हुए 6 से 18 साल के बच्चों को नियमों में छूट देकर प्रवेश दें।

सब पढ़ें, सब बढ़ें छूटी पढ़ाई में मदद करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को दिया निर्देश, कार्ययोजना तैयार करने को कहा

स्कूल नहीं जा रहे बच्चों का पता लगाने अब घर-घर सर्वे

नई दिल्ली (एजेंसी)। कोरोना काल ने सबसे ज्यादा जिसको प्रभावित किया है वे हैं -स्कूली बच्चे। वे चाहे छोटी क्लास के हों या बड़ी कक्षाओं के। महामारी के दौर में उनकी पढ़ाई सबसे ज्यादा बाधित रही। स्कूल नहीं जा पाए। स्कूली गतिविधियां प्रभावित रहीं। इन सबके बीच सरकार ने ऐसे बच्चों का पता लगाने को कहा जो स्कूल नहीं जा पाए। इसके लिए घर-घर सर्वेक्षण कराने का राज्यों को निर्देश दिया है। सरकार ने बच्चों को फेल करने के नियम में शिथिलता बरतने के लिए भी कहा है।

शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने कोरोना महामारी के प्रभाव को कम करने के प्रयास के तहत राज्यों से कहा है कि वे घर-घर जाकर बच्चों का सर्वेक्षण तथा उनका स्कूलों में पंजीकरण कराने की योजना तैयार करें। अधिकारियों ने बताया कि मंत्रालय ने इस साल बच्चों को फेल करने के नियमों में ढील देने की भी सिफारिश की है।

इसके साथ ही सरकार ने जिन बच्चों की पढ़ाई छूटी है उनके लिए ब्रिज कोर्स शुरू करने को भी कहा है। स्कूल खुलने के बाद उनके लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करने को कहा है ताकि वे बिल्कुल तनाव महसूस न करें। मंत्रालय ने उनकी समझ बढ़ाने के लिए प्रयास करने, पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें पढ़ने तथा रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहित करने को भी कहा है।

पहल

कोरोना के चलते बच्चों को फेल करने के नियम शिथिल करने को कहा

तनावमुक्त माहौल के अतिरिक्त ब्रिज कोर्स शुरू करने की भी सिफारिश

स्कूल से घर लौटते बच्चे। ● फाइल फोटो

उद्देश्य : बिना परेशानी बच्चे पढ़ते रहें

अधिकारियों ने बताया कि यह सिफारिश महामारी के दौरान स्कूल न जा पाने वाले बच्चों की पहचान करने, उनकी शिक्षा जारी रखने के उद्देश्य से की गईहै। मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि ड्रॉपआउट बढ़ने, पंजीकरण कमहोने व पढ़ाई के नुकसान की समस्या से निपटने के लिए राज्यों को उचित नीति बनाने की जरूरत है।

सिफारिश : बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए बने कार्ययोजना

अधिकारी ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सिफारिश की गईहै कि छह से 18 वर्ष की आयु के उन बच्चों की पहचान के लिएघर-घर सघन सर्वेक्षण किया जाए जो स्कूलों से दूर हैं। साथ ही उनका स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए एक कार्ययोजना तैयार की जाए। मंत्रालय ने विद्यार्थियों को हर मदद मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं।

Badri Gautam

आज से महाविद्यालयों में लगेंगी अंतिम वर्ष की नियमित कक्षाएं

कार्यालय प्रतिनिधि| रीवा

हायर एजुकेशन के निर्देश के बाद आज से महाविद्यालयों में अंतिम वर्ष की नियमित कक्षाएं लगेंगी। निर्धारित गाइडलाइन का पालन करते हुए सोमवार से छात्र महाविद्यालय में अध्यापन के लिए आ सकते हैं। हालांकि आज से शुरू हो रही क्लास में केवल अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ही खोली जा रही है। जिले के महाविद्यालय भी कॉलेज खोलने की तैयारी में लगे हुए है। फिलहाल 10 महीने बाद आज से खुल रहे महाविद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति की स्थिति क्या होगी इसका पता सोमवार को ही चल पाएगा। उल्लेखनीय है कि हायर एजुकेशन के निर्देश के तहत 1 से 10 जनवरी तक फाइनल ईयर के छात्रों के लिए प्रैक्टिकल क्लास शुरू करने का निर्देश दिया गया था।

इन गाइडलाइन का पालन करना होगा अनिवार्य

क्लास अटेंड करने आने वाले छात्रों को गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। बताया गया है कि छात्रों को 6 फिट दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। इसके अलावा 50 प्रतिशत छात्र ही कॉलेज आ सकते हैं। महाविद्यालय प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि 50-50 प्रतिशत छात्र ही कॉलेज में क्लास अटेंड करे। छात्रों को मास्क लगाना होगा। पहचान पत्र पहनना होगा अनिवार्य। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी।

उपस्थिति की नहीं रहेगी बाध्यता

आज से शुरू हो रही महाविद्यालयों क्लास में विद्यार्थियों की उपस्थिति स्वैच्छिक होगी। छात्रों पर 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं रहेगी। छात्रवृत्ति पर भी यह नियम लागू होगा।

महाविद्यालयों के लिए होगी चुनौती• जिले के महाविद्यालयों की यह जवाबदारी होगी की वह निर्धारित गाइडलाइन का पालन कराते हुए कक्षा संचालित करे। अब महाविद्यालयों के छात्रों से 6 फिट की दूरी और मास्क का हर समय इस्तेमाल करा पाना जिले के महाविद्यालयों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा।

सहमति पत्र लाना होगा अनिवार्य• कॉलेज आने वाले छात्रों को अभिभावक और अपना सहमति पत्र लाना अनिवार्य होगा। बिना सहमति पत्र के विद्यार्थियों को कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कॉलेज सूत्रों की माने तो सहमति पत्र से संबंधित प्रारूप विद्यार्थियों को भेज दिया गया है। महाविद्यालय प्रबंधन से छात्रों के मोबाइल और मेल आईडी में प्रारूप भेज कर विद्यार्थियों को इसे साथ में कॉलेज लेकर आने की बात कही है। सहमति पत्र में विद्यार्थी और अभिभावक द्वारा कॉलेज में क्लास अटेंड करने की बात कही गई है।

21 से शुरू हो सकती हैं कक्षाएं

बताया गया है कि आगामी 21 जनवरी से प्रथम और द्वितीय वर्ष की ऑफलाइन कक्षा शुरू हो सकती है। हालांकि इसके लिए प्रशासन द्वारा बनाई गई क्राइसिस मैनेजमेंट की अनुमति आवश्यक होगी। बताया गया है कि क्राइसिस मैनेजमेंट द्वारा जिले में कोरोना इफेक्ट की स्थिति को देखते हुए इस संबंध में सहमति या असहमति का निर्णय लेगा। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी 21 जनवरी से प्रथम व द्वितीय वर्ष की भी कक्षाएं शुरू हो सकती है।

Badri Gautam

ऑनलाइन स्विमिंग व फुटबॉल सिखाने के नाम पर फीस वसूल रहे निजी स्कूल

तीन माह की पूरी फीस मांग रहे स्कूल संचालक, परेशान अभिभावकों ने की शिकायत

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। राजधानी के कई निजी स्कूल संचालक परीक्षा शुल्क के साथ अब स्विमिंग और फुटबॉल सहित अन्य गतिविधियों की फीस जोड़कर मांग रहे हैं। इसके अलावा अभिभावकों से परीक्षा और प्रोजेक्ट जमा करने के नाम पर भी फीस वसूली जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) और बाल आयोग के पास इस तरह की शिकायतें अभिभावकों ने की हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें डीपीएस स्कूल की डीईओ के पास पहुंची हैं, लेकिन कार्रवाई न होने के कारण मनमानी जारी है।

अभिभावकों ने बताया कि डीपीएस ने तो ऑनलाइन शिक्षण के साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधि भी ऑनलाइन करा दीं और सालभर की पूरी फीस मांगी जा रही है। वहीं कुछ स्कूल संचालकों द्वारा स्मार्ट क्लास की भी फीस ली जा रही है, जबकि यह शिक्षण शुल्क में शामिल होना चाहिए था। जवाहरलाल नेहरू स्कूल के सातवीं कक्षा का शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क 3205 रुपये मांगा जा रहा है। अभी तक तीन माह की फीस 2200 रुपये ली जा रही थी। डीपीएस में पढ़ने वाले एक बच्चे के अभिभावक ने बताया कि उसके पास स्कूल से दिसंबर में फोन आया था कि बच्चे की स्वीमिंग की क्लास लगाई जाएगी। उसकी फीस भी ली गई, लेकिन उन्होंने ठंड के कारण बच्चे को स्विमिंग नहीं कराई। इसके अलावा डांस, म्यूजिक, फुटबॉल की ऑनलाइन क्लास लगाई गईं। इस तरह ऑनलाइन एक्टिविटी से बच्चे ने कुछ भी नहीं सीखा, लेकिन फीस पूरी देनी पड़ी।

राजधानी में स्कूलों की स्थिति

सीवीएसई स्कूलों की संख्या: 100
बच्चों की संख्या : दो लाख बच्चे

यह है स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश

कोरोना संक्रमण काल में जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक का सिर्फ शिक्षण शुल्क देना होगा। अन्य कोई फीस नहीं लगेगी। वहीं 18 दिसंबर से नौवीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं तो स्कूल शिक्षा विभाग ने जनवरी से गतिविधियों की भी फीस लेने के निर्देश दिए हैं। लेकिन निर्देश में लिखा है कि अगर स्कूल में लैब, कंप्यूटर आदि गतिविधियां कराईजा रही हैं तो ही इसकी फीस ले सकते हैं।

कहां कितनी फीस बढ़ी

जवाहर लाल नेहरू (7वीं) : पहले 2200 रुपये थी अब 3205 रुपये (तीन माह की)

सागर पब्लिक स्कूल (11वीं) : 78 हजार कोई बदलाव नहीं। (सालाना फीस)

विंध्याचल अकेडमी (10वीं) : पिछले साल की फीस 36 हजार, इस साल की 39 हजार (सालभर की)

डीपीएस : एनुअल फीस-20 हजार, शिक्षण शुल्क-85 हजार (साल भर की), कोई बदलाव नहीं।

"मेरा बेटा दसवीं में विंध्याचल एकेडमी में पढ़ता है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल स्कूल संचालक ने कोरोनाकाल में तीन हजार रुपये बढ़ा दिए गए।

-विनोद गंगराड़े, अभिभावक

छठवीं की एनुअल फीस एक बच्चे की 5200 रुपये मांग रहे हैं। इस साल स्कूल खुले नहीं हैं, फिर भी फीस की मांग कर रहे हैं। साल भर की फीस में कोई रियायत नहीं मिली है।

-आनंद श्रीवास्तव, अभिभावक

डीपीएस स्कूल की शिकायत मिली थी। उसका निराकरण कराया, अन्य स्कूलों की भी शिकायतें मिली हैं। अगर कोई अभिभावक शिकायत करेगा तो कार्रवाई की जाएगी।

-नितिन सक्सेना, जिला शिक्षा अधिकारी"

Badri Gautam

फर्स्ट ईयर विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन का सत्यापन करने में कॉलेज पिछड़े

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज-विवि (एसएससी) के तहत 2020-21 सत्र में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति मिलना है। मगर अभी तक कॉलेजों ने छात्रवृत्ति आवेदनों का सत्यापन नहीं किया है। इसके चलते विद्यार्थियों को राशि मिलने में देर होने लगी है। लापरवाही को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों को फटकार लगाई है और जल्द ही सत्यापन की प्रक्रिया कर पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। प्रक्रिया 20 जनवरी तक पूरी करना है।

कोरोना की वजह से कॉलेज व विश्वविद्यालय में चार महीने देरी से दाखिले हुए हैं। नवंबर तक 2020-21 सत्र के लिए विद्यार्थियों को प्रवेश दिए हैं। बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम और एमएससी फर्स्ट ईयर में दाखिला ले चुके विद्यार्थियों को केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति योजना का लाभ देना है। दिसंबर तक इन छात्र-छात्राओं के आवेदनों का सत्यापन कॉलेज व विश्वविद्यालय को करना था, लेकिन दिसंबर आखिरी सप्ताह में विभाग ने काउंसलिंग का अतिरिक्त चरण रखा। इसके चलते आवेदन को सत्यापित करने की प्रक्रिया रोक दी।

यूजीसी ने पहले 31 दिसंबर 2020 तक आवेदन भेजने के निर्देश दिए हैं। कॉलेजों की लापरवाही की वजह से यूजीसी और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी नाराज हैं। बाद में 20 जनवरी तक आवेदन को सत्यापित कर स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपडेट करना है। अधिकारियों के मुताबिक प्रदेशभर में यूजी कोर्स में करीब चार लाख विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। 20 जनवरी तक पंजीयन बंद होगा।

Badri Gautam

जिन पालकों को फीस भरने में परेशानी आ रही, वे आवेदन दें

प्रतिमाह भी फीस जमा करा सकते हैं : वैष्णव ट्रस्ट

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। वैष्णव ट्रस्ट के स्कूलों की फीस को लेकर पालकों की नाराजगी सामने आई थी। इसके बाद ट्रस्ट ने कहा है कि जिन्हें फीस भरने में कोई परेशानी है, वे हमें आवेदन देकर बताएं।

ट्रस्ट के अध्यक्ष पुरुषोत्तमदास पसारी ने कहा, हम पहले भी आर्थिक रूप से कमजोर पालकों को फीस में राहत देते रहे हैं। कई पालक ऐसे होते हैं जो आर्थिक परेशानी के चलते फीस नहीं भर पाते हैं उनकी फीस भी माफ की है। ऐसे में पालकों को यह बात समझनी चाहिए कि ट्रस्ट हमेशा से आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाता रहा है। लॉकडाउन में संस्थान ने एक भी स्टॉफ कम नहीं किया, न किसी के वेतन में कटौती की। ऐसे में स्कूल संचालन के लिए फीस लेना जरूरी है। करीब 70 फीसद पालक फीस भर भी चुके हैं। अगर किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वे आवेदन दे सकते हैं। हम ऐसे मामलों में राहत देने पर विचार करेंगे। उल्लेखनीय है कि वैष्णव ट्रस्ट के स्कूलों की आधी फीस माफ करने और ऑनलाइन क्लास बंद होने पर पालक कुछ दिन से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। पसारी का कहना है कि हम अप्रैल से लगातार ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। हमने पालकों को प्रति महीने फीस भरने की राहत भी दी है। कर्मचारियों और अन्य खर्चों की पूर्ति फीस से की जाती है। इसी से कर्मचारियों को वेतन मिलता है।

Badri Gautam

नौवीं और ग्यारहवीं के बच्चों को दबाव देकर बुला रहे थे स्कूल

सेंटपॉल स्कूल

- **जांच के लिए पहुंचे एसडीएम और जिला शिक्षा अधिकारी**
- **पालकों की अनुमति मिलने के बाद ही विद्यार्थियों को स्कूल बुलाएं**

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। सेंटपॉल हायर सेकंडरी स्कूल में नौवीं और 11वीं के विद्यार्थियों को दबाव देकर पढ़ने के लिए स्कूल बुलाया जा रहा था। कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर रविवार को यहां जांच के लिए एसडीएम व जिला शिक्षा अधिकारी रविकुमार सिंह पहुंचे।

अवकाश होने के कारण विद्यालय बंद पाया गया। जिला शिक्षा अधिकारी विद्यालय परिसर में रह रही उप प्राचार्य सिस्टर पेट्रिसिया से मिले और अभिभावकों की शिकायत के बारे में बताया। इस पर उप प्राचार्य ने कहा कि अभिभावकों की अनुशंसा पर ही विद्यार्थियों को स्कूल बुलाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को माता-पिता या अभिभावकों की अनुमति से विद्यालय में आने की अनुमति प्रदेश शासन के आदेश के अनुसार दी गई है। इसी सिलसिले में जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूल संचालकों को एक बार फिर निर्देशित किया है कि 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को माता-पिता या अभिभावकों की अनुमति मिलने पर ही स्कूल बुलाया जाए। स्कूल में कोविड प्रोटोकॉल की एसओपी का पालन किया जाए। जो स्कूल निर्देशों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Badri Gautam

एलएलएम की परीक्षा पर तीन दिन में विश्वविद्यालय लेगा फैसला

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। एलएलएम की परीक्षा को लेकर खड़े हुए विवाद को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इस सप्ताह सुलझा सकता है। विद्यार्थियों की आपत्ति के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मंगलवार को बैठक रखी है, जिसमें विधि संकाय के डीन, कॉलेज प्राचार्य और बोर्ड ऑफ स्टडी के चेयरमैन परीक्षा के मुद्दे पर अपनी-अपनी राय देंगे। उसकी रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक तीन दिन के भीतर परीक्षा को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी।

एलएलएम की ऑनलाइन और ओपन बुक पद्धति से परीक्षा को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। असमंजस में पड़े विद्यार्थियों ने बीते सप्ताह विवि में प्रदर्शन किया और कहा कि एलएलएम पाठ्यक्रम सीधे तौर पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ) के दायरे में नहीं आता है। इनकी परीक्षा करवाने का अधिकार उच्च शिक्षा विभाग के पास है। ऐसे में बीसीआइ का परीक्षा को लेकर आदेश एलएलएम पर लागू नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने तीन व पांच वर्षीय कोर्स के लिए गाइडलाइन जारी की थी। जबकि एलएलएम सिर्फ दो वर्षीय पाठ्यक्रम है। विद्यार्थियों की मानें तो विभाग ने यूजी-पीजी की परीक्षा को लेकर पहले ही आदेश दिया था। उसके मुताबिक ओपन बुक पद्धति से विद्यार्थियों ने असाइनमेंट भी जमा कर दिए थे। मगर अभी तक उसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। विद्यार्थियों ने अपनी समस्या परीक्षा नियंत्रक डॉ. अशेष तिवारी और परीक्षा विभाग के डिप्टी रजिस्ट्रार प्रज्जवल खरे को बताई थी। शुक्रवार को कुलपति डॉ. रेणु जैन, प्रभारी रजिस्ट्रार अनिल शर्मा और परीक्षा नियंत्रक व डिप्टी रजिस्ट्रार के बीच बातचीत हुई। जहां उन्होंने सभी लॉ कॉलेजों के प्राचार्यों, डीन और बोर्ड ऑफ स्टडी के चेयरमैन से राय मांगी है।

असाइनमेंट से मूल्यांकन

एलएलएम में लगभग 200 विद्यार्थी हैं, जिन्होंने पहले ही असाइनमेंट जमा कर दिए हैं। जिन विद्यार्थियों ने असाइनमेंट जमा किए हैं उनका मूल्यांकन उसके आधार पर करने को लेकर सहमति बनी है। बताया जाता है कि विश्वविद्यालय इनका रिजल्ट जारी कर सकता है। मगर पहले डीन-प्राचार्य की राय मिलने का इंतजार कर रहा है।

Badri Gautam

लॉ कोर्स की ऑनलाइन परीक्षा के लिए विवि रखेगा दो सर्वर

इंदौर। विभिन्न लॉ कोर्स की ऑनलाइन परीक्षा की रिहर्सल देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने कर ली है। मॉक टेस्ट के दौरान विश्वविद्यालय के सामने कुछ दिक्कतें आई। इसे निपटने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब दो सर्वर रखने का फैसला लिया है। ताकि परीक्षा बेहतर ढंग से संचालित हो सके। परीक्षाओं का शेड्यूल 15 जनवरी तक जारी किया जाएगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश के बाद अब विश्वविद्यालय लॉ कोर्स की ऑनलाइन परीक्षा करवाने जा रहा है, जिसमें बीएएलएलबी, बीकॉमएलएलबी, बीबीएएलएलबी, एलएलबी के विभिन्न सेमेस्टर शामिल हैं। लगभग आठ हजार विद्यार्थियों की परीक्षा ली जाएगी। यह पहला मौका है जब विश्वविद्यालय प्रशासन ऑनलाइन पद्धति से परीक्षा करवाने जा रहा है। छह जनवरी को परीक्षा की रिहर्सल मॉक टेस्ट के जरिए की। यहां ज्यादातर विद्यार्थियों को ऑनलाइन कॉपी सबमिशन को लेकर लिंक नहीं मिली। एक साथ सात हजार विद्यार्थी जोड़ने से सर्वर डाउन हो गया था। इस परेशानी से निपटने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने दो सर्वर के जरिए परीक्षा करवाने पर जोर दिया है। आइटी सेंटर से भी चर्चा हो चुकी है। विवि ने परीक्षा के लिए अलग टीम बनाई है।

कोरोना के कारण प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में 13 हजार विद्यार्थी कम हुए

महामारी का असर

- पिछले सालों में 40 हजार से ज्यादा विद्यार्थी होते रहे हैं शामिल
- इस वर्ष मात्र 27 हजार विद्यार्थी ही शामिल हुए इस परीक्षा में

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) द्वारा आयोजित की जाने वाली प्री एग्रीकल्चर टेस्ट (पीएटी) के परिणाम जारी हो गए हैं। प्रदेश के सरकारी एग्रीकल्चर कॉलेजों की 1100 सीटों पर प्रवेश के लिए अगले सप्ताह काउंसिलिंग कार्यक्रम जारी हो जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। इस वर्ष काफी कम विद्यार्थियों ने पीएटी दी थी। इसके पीछे कोरोना महामारी को कारण बताया जा रहा है। हर साल प्रदेश से 40 हजार से ज्यादा प्रतिभागी शामिल होते रहे हैं, लेकिन इस बार 27 हजार ने ही परीक्षा दी थी। इससे सरकारी कॉलेजों में पीएटी में वेहतर अंक लाने वाले विद्यार्थियों को आसानी से सीट मिल जाएगी।

इंदौर में प्रवेश लेना चाहते हैं विद्यार्थी : परीक्षा विशेषज्ञ मदन धाकड़ का कहना है कि ज्यादातर विद्यार्थी जबलपुर और ग्वालियर के अलावा इंदौर के एग्रीकल्चर में प्रवेश लेने की इच्छा रखते हैं। कई विद्यार्थी इंदौर के एग्रीकल्चर कॉलेज में इसलिए भी प्रवेश लेना चाहते हैं क्योंकि यहां रहते हुए अन्य परीक्षाओं की तैयारी भी विद्यार्थी कर लेते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि प्रेक्टिकल पढ़ाई के नजरिए से देखा जाए तो जबलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज भी अच्छा संस्थान है। कई विद्यार्थी जो खुद की खेती को आगे बढ़ाना चाहते हैं वे भी बढ़ी संख्या में एग्रीकल्चर क्षेत्र में अच्छे संस्थानों से डिग्री लेने लगे हैं।

Badri Gautam

स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के पास आनलाइन नामांकन करने का मौका 18 तक

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी ने स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के नामांकन की लिंक आनलाइन खोल दी है। 18 जनवरी तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। जो भी विद्यार्थी इस अवधि में अपना नामांकन नहीं दर्ज करवा पाएगा उसे आगामी परीक्षाओं से वंचित होना पड़ सकता है। प्रशासन की तरफ से इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है।

कुलसचिव दीपेश मिश्रा ने बताया कि सत्र 2020-21 में प्रवेश लेने वाले सभी स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को परीक्षा पूर्व यूनिवर्सिटी में नामांकन करवाना अनिवार्य है। नामांकन के आधार पर ही विद्यार्थियों को परीक्षा आवेदन करने का अवसर मिलेगा।

ये है शुल्क और तिथि

- नामांकन शुल्क 330 रुपये है। बिना विलंब शुल्क के 18 जनवरी तक नामांकन किया जा सकता है।
- विलंब शुल्क 330 रुपये के साथ 22 जनवरी तक नामांकन आनलाइन किया जा सकता है।
- 22 जनवरी तक विद्यार्थी नामांकन फार्म की प्रति कॉलेजों में जमा कर सकते हैं।
- 25 से 27 जनवरी के मध्य तक कॉलेजों को दस्तावेजों का सत्यापन कर यूनिवर्सिटी को भेजना होगा।

Badri Gautam

इन विषयों के विद्यार्थी को कराना होगा नामांकन: रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी से संबंद्ध कॉलेजों में बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीबीए, बीकॉम आनर्स, एलएलबी, बीएलएलएलबी, एलएलएम, एमएसडब्ल्यू, एमएचएससी, एमकॉम, एमएससी, एमए आदि विषयों के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को नामांकन आनलाइन करवाना होगा। इसके अलावा स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से नामांकन का नवीनीकरण करवाना होगा।

दक्षता परीक्षा : पूर्व बीआरसी की जगह बैठा दूसरा शिक्षक

मुरैना (नप्र)। शिक्षक दक्षता परीक्षा में मुरैना के पूर्व बीआरसी ने अपनी जगह एक शिक्षक को बैठा दिया। जिला शिक्षा अधिकारी ने फर्जी परीक्षार्थी को पकड़ लिया, लेकिन इस मामले में राजनीतिक दबाव के कारण भी कार्रवाई नहीं हुई है। मामला कलेक्टर तक जा पहुंचा है।

जिन स्कूलों की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 40 फीसद से कम रहा था, उन स्कूलों के शिक्षकों के लिए शिक्षक दक्षता परीक्षा कराई गई थीं। 4 जनवरी को मुरैना उत्कृष्ट स्कूल क्रमांक एक में पूर्व बीआरसी राजेंद्र सिंह सिकरवार को भी परीक्षा देनी थी। उन्होंने एक शिक्षक को बुलाकर अपनी जगह बैठा दिया। इसी दौरान जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष शर्मा वहां पहुंच गए और शिक्षक को पकड़ लिया। शिक्षक ने अपनी नौकरी, परिवार, मान-सम्मान का हवाला देते हुए डीईओ सुभाष शर्मा के पांव पकड़ लिए। मौके पर सुभाष शर्मा ने कार्रवाई की बात कही, लेकिन मामले में सुमावली और ग्वालियर से जुड़े नेताओं का दवाब में पूर्व बीआरसी को नोटिस तक जारी नहीं हुआ।

> "मेरे क्या हाथ-पांव टूट गए हैं तो किसी और को परीक्षा में बैठाऊंगा। मैंने किसी को नहीं बैठाया। विभाग में इसे लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं चलने दो, इससे मुझे क्या करना है।
>
> **राजेंद्र सिंह सिकरवार**, पूर्व बीआरसी

> हां पूर्व बीआरसी राजेंद्र सिंह सिकरवार ने अपनी जगह किसी और को परीक्षा में बैठाया था। मैंने उसे जाकर पकड़ा था और उससे कापी ले ली, इस दौरान वह भाग गया। कह नहीं सकता कि वह शिक्षक था या आम युवक। इसमें जो कार्रवाई बनती है करेंगे।
>
> **सुभाष शर्मा**, डीईओ, मुरैना

Badri Gautam

आनलाइन नहीं, स्थानीय स्तर पर खरीदी

अव्यवस्था ● स्कूलों में सामग्री क्रय करने राशि आवंटित, प्रक्रिया को लेकर लग रहे आरोप

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। स्कूलों में विकासखंड अधिकारियों को स्कूलों के लिए उपयोगी सामग्री क्रय करने के लिए लगभग 5-5 लाख रुपये प्रति विकासखंड का वजट आवंटित हुआ। इस राशि से 15 जनवरी तक खरीदी की जानी है लेकिन खरीदी प्रक्रिया को लेकर कई आरोप लग रहे हैं।

विभागीय अधिकारियों को आनलाइन शासन के जैम पोर्टल के वजाए सीधे दुकानों से सामग्री क्रय की जा रही है, जिस वजह से उसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वता दें कि विभाग ने फर्नीचर, पुस्तक, फोटोकापी मशीन, कंप्यूटर आदि क्रय करने के लिए करीव 49 लाख रुपये का आवंटन किया हुआ है। आनलाइन वीडियो कांफ्रेंस में 15 जनवरी तक खरीदी करने के निर्देश मिले हैं। विभागीय स्तर पर अधिकारियों ने जैम की वजाए इस राशि से निविदा के माध्यम से खरीदी की जा रही है। वताया जाता है कि स्थानीय स्तर पर अपनाई जा रही खरीदी प्रक्रिया में गुणवत्ता को लेकर प्रश्नचिन्ह लग रहा है। इधर, विकासखंड शिक्षा अधिकारी अंजनी सेलट ने कहा कि नियमानुसार ही निविदा के जरिए खरीदी की प्रक्रिया की जा रही है। उन्होंने बताया कि जो जरूरी सामग्री है उसकी खरीददारी की जा रही है।

जैम में क्या: विभागों में खरीदी के लिए शासन स्तर पर आनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। जिसे जैम कहा जाता है इस पोर्टल पर गुणवत्ता के उत्पाद और विक्रेता ही पंजीकृत है। हर वस्तु का निर्धारित दाम रखा गया है। इसके लिए किसी तरह की कोई निविदा किए बगैर ही सीधे आनलाइन आर्डर दिया जा सकता है। ये शासन से मान्य प्रक्रिया है। निविदा के माध्यम से भी खरीदी संभव है लेकिन इसमें सामग्री के दाम को लेकर अंतर देखने में मिलता है।

नए शैक्षणिक सत्र में छठवीं-आठवीं के बच्चे जमीन पर नहीं, बेंच पर बैठेंगे

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। नए शैक्षणिक सत्र में सरकारी स्कूलों के कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों को वेंच में बैठाया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संवंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। विभागीय स्तर पर स्कूल खोलने को लेकर प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में माध्यमिक स्कूलों को फर्नीचर उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है।

नामांकन के आधार पर स्कूलों को मिलेंगे फर्नीचर : एक परिसर एक शाला के स्कूलों में छठवीं से आठवीं तक के विद्यार्थियों का नामांकन एवं विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर फर्नीचर उपलब्ध कराया जाना है। इसके आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इस संवंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने जिला मिशन संचालकों को निर्देश जारी किए हैं। छठवीं से आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर उपलब्ध कराया जाना है। यू-डाइस 2019-20 के अनुसार कक्षा छठवीं से आठवीं तक के विद्यार्थियों का नामांकन एवं विद्यार्थियों की संख्या के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं।

लंबे समय से चल रही थी कवायद : स्कूल शिक्षा विभाग लंवे समय से माध्यमिक स्कूल के विद्यार्थियों को डेस्क-वेंच में वैठाने की कवायद में जुटा था। हालांकि हर वार किसी न किसी कारण से सरकारी स्कूलों में डेस्क-वेंच की व्यवस्था लागू नहीं हो पा रही थी।

जिलेवार जारी किए गए आंकड़े: राज्य शिक्षा केंद्र ने जवलपुर परियोजना समन्वयक सहित प्रदेश के अन्य अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए एक पत्र जारी किया है जिसमें जिलेवार आंकड़ा दिया गया है। आंकड़ों के अनुसार ही जिलों के विद्यार्थियों के लिए डेस्क-वेंच खरीदनी पड़ेगी।

Badri Gautam